

प्रधानमंत्री कार्यालय

झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन के शुभारम्भ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विस्तार पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 08 MAR 2018 7:50PM by PIB Delhi

विशाल संख्या में पधारे हुए माताएं, बहनें, भाइयो और नौजवान मित्रों।

आज 8 मार्च, पूरा विश्व 100 साल से भी अधिक समय से अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन आज पूरा हिन्दुस्तान झुंझुनू के साथ जुड़ गया है। देश के हर कोने में टेक्नोलॉजी की मदद से ये झुंझुनू का भव्य दृश्य पूरे देश के कोने-कोने में पहुंच रहा है।

मैं झुंझुनू ऐसे ही नहीं आया हूं, सोच-विचार करके आया हूं; और आया क्या आपने मुझे खींच लिया है। आपने मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया है। और मजबूरी इस बात की थी कि आपने- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ- इस अभियान को इस जिले ने जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहां के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के आ जाते हैं।

अभी वसुंधरा जी वर्णन कर रही थीं कि कैसे ये वीरों की भूमि है, इस भूमि की क्या ताकत रही है, और इसलिए चाहे समाज सेवा का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे दान-पुण्य का काम हो, चाहे देश के लिए मर-मिटने की बात हो; ये जिले ने ये सिद्ध कर दिया है- युद्ध हो या अकाल हो, झुंझुनू झुकना नहीं जानता, झुंझुनू जूझना जानता है। और इसलिए झुंझुनू की धरती से आज जिस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को झुंझुनू से भी प्रेरणा मिलेगी, देश को यहां से भी एक नई ताकत मिलेगी।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ- अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी-कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परम्पराएं, शास्त्रों में उत्तम से उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक- सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ-पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है; उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है।

मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और कई दशकों से एक विकृत मानसिकता के कारण, एक गलत सोच के कारण, सामाजिक बुराइयों के कारण हमने बेटियों को ही बलि चढ़ाने का रास्ता चुन लिया। जब ये सुनते हैं कि हजार बेटों के सामने कहीं 800 बच्चियां हैं, 850 बच्चियां हैं, कहीं 900 बच्चियां हैं- ये समाज की क्या दुर्दशा होगी, कल्पना कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष की समानता से ही ये समाज का चक्र चलता है, समाज की गतिविधि बढ़ती है।

कई दशकों से बेटियों को नकारते रहे, नकारते रहे; मारते रहे। उसी का नतीजा है कि समाज में एक असंतुलन पैदा हुआ। मैं जानता हूं एकाध पीढ़ी में ये सुधार नहीं होता है। चार-चार, पांच-पांच पीढ़ियों की बुराइयां आज इकट्ठा हुई हैं। पुराना जो घाटा है, वो घाटा दूर करने में समय लगेगा, वो हर कोई समझता है। लेकिन अब तो हम तय करें कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां भी पैदा होंगी।

जितने बेटे पलेंगे उतने ही बेटियां पलेंगी। बेटा-बेटी, दोनों एक समान; इस भाव को ले करके अगर चलेंगे तो चार-पांच-छह पीढ़ी में बुरा हुआ है, वो शायद हम दो या तीन पीढ़ी में ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त है- अभी जो बच्चे पैदा होंगे, उसमें कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए।

और मुझे खुशी की बात है कि आज जिन जिलों को सम्मानित करने का अवसर मिला, उन पहले दस जिलों ने इस काम को बखूबी निभाया है। ये जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उसमें वो बेटों की बराबरी में बेटियों को लाने में सफल हुए हैं। आज जिनको सम्मान करने का अवसर मिला उन जिलों को, उस राज्य को, उस टीम को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने इस पवित्र कार्य को अपने जिम्मे लिया।

और मैं और भी देश के सभी अधिकारियों से, सरकार के सभी हमारे साथियों से, मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि इसे जन-आंदोलन बनाना होगा। जब तक एक-एक परिवार जुड़ता नहीं है और जब तक Mother-in-law-सास उसका नेतृत्व नहीं संभालती है, इस काम को समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर Mother-in-law इसको संभाल लेती हैं कि बेटी चाहिए और एक बार साफ कह दें कि घर में बेटी चाहिए, किसी की ताकत नहीं है कि वो बेटी के साथ कोई अन्याय कर सके। और इसलिए हमें एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमें जन-आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा।

भारत सरकार ने दो वर्ष पूर्व हरियाणा- जहां पर अनुपात बहुत ही चिंताजनक था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हरियाणा में कार्यक्रम किया। हरियाणा की धरती पर जा करके ये बात बताना कठिन था। मेरे अफसरों ने मुझे सुझाव दिया था कि साहब वहां तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां जाएंगे तो और नया ही कुछ गलत हो जाएगा। मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा तकलीफ है वहीं से शुरू करूंगा। और आज मैं हरियाणा को बधाई देता हूँ, उन्होंने पिछले दो साल में परिस्थितियों में इतनी तेजी से सुधार किया है।

जन्म के समय बेटियों की संख्या में जो बढ़ोत्तरी हुई है वो अपने आप में एक नया विश्वास एक नई आशा पैदा करता है। और ये जो पिछले दो साल का अनुभव है, उसमें जो सफलता मिली है, उसे ध्यान में रख करके आज 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत सरकार ने अब वो योजना 160-161 districts तक ही नहीं, हिन्दुस्तान के सभी districts के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। उसके लिए- वहां स्थिति अच्छी भी होगी, ज्यादा अच्छी कैसे हो, उसके लिए भी काम किया जाएगा।

हमें अपने-आप को पूछना पड़ेगा। ये जो पुरानी सोच रही है कि बेटी कभी-कभी लगता है बोझ होती है। आज अनुभव कहता है, हर घटनाएं बताती हैं; बेटी बोझ नहीं, बेटी ही तो पूरे परिवार की आन-बान-शान है।

हिन्दुस्तान में देखिए आप- जब सेटेलाइट, आसमान में हम जाते हैं, सुनते हैं कि आज सेटेलाइट गया, मंगलायन हुआ, ठिकना हुआ; और जब देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे देश की तीन महिला साइंटिस्टों ने space technology में इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, तब पता चलता है कि बेटियों की ताकत क्या होती है। जब झुंझुनू की ही एक बेटी फाइटर जहाज चलती है तो लगता है, हां बेटियों की ताकत क्या होती है। ओलिम्पिक में जब गोल्ड मैडल ले करके कोई आते हैं, मैडल ले करके आते हैं और पता चलता है कि लाने वाली बेटियां हैं तो पूरे देश का सीना गर्व से भर जाता है कि हमारी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं।

और जो लोग ये मानते हैं कि बेटा है तो बुढ़ापे में काम आएगा, स्थिति कुछ अलग ही है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, जहां बूढ़े मां-बाप हों, चार-चार बेटे हों, बेटों को अपने बंगले हों, गाड़ियों की भरमार हो, लेकिन बाप और मां अनाथाश्रम में बुढ़ावा बिताते हों, ऐसे परिवार हमने देखे हैं; और वैसे भी परिवार

देखे हैं कि बेटी, बूढ़े मां-बाप की इकलौती बेटी, मां-बाप को बुढ़ापे में तकलीफ न हो, इसलिए रोजगार करती है, धंधा-रोजगार करती है, नौकरी जाती है, मेहनत करती है, शादी तक नहीं करती है; ताकि बुढ़ापे में मां-बाप को तकलीफ न हो और मां-बाप के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करती है।

और इसलिए समाज में जो सोच बनी है, ये जो विकृति घर कर गई है, उस विकृति से हमें बाहर आना है। और इसको एक सामाजिक आंदोलन, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सफलता-विफलता को कोई सरकार को दोष दे दे, ठीक है वो काम करने वाले करते रहें; लेकिन इसकी सफलता का आधार, हर परिवार का संकल्प ही सफलता का कारण बन सकता है, और इसलिए जब तक बेटा-बेटी एक समान, बेटी के लिए गर्व का भाव, ये हमारे जेहन में नहीं होगा; तब तक मां की गोद में ही बेटियों को मार दिया जाएगा।

18वीं शताब्दी में बेटी को दूध-पीती करने की परम्परा थी। एक बड़े बर्तन में दूध भर करके बेटी को डुबो दिया जाता था। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी उन 18वीं शताब्दी के लोगों से भी कभी-कभी बुरे लगते हैं। क्योंकि 18वीं शताब्दी में कम से कम उस बेटी को जन्म दिए जाने का हक रहता था, उसको अपनी मां का चेहरा देखने का सौभाग्य मिलता था, उस मां को अपनी बेटी का चेहरा देखने का सौभाग्य मिलता था, इस पृथ्वीपर उसको कुछ पल के लिए क्यों न हो- सांस लेने का अवसर मिलता था और बाद में वो महापाप कर-करके समाज की सबसे बड़ी बुराई वाला काम कर दिया जाता था।

लेकिन आज-आज तो उससे भी ज्यादा बुरा करते हैं कि मां के पेट में ही, न मां ने बेटी का मुंह देखा है न बेटी ने मां का देखा है- आधुनिक विज्ञान की मदद से मां के पेट में ही बच्ची को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा बुरा कोई पाप नहीं होगा। जब तक हम मानेंगे नहीं कि बेटी हमारी आन-बान-शान है, तब तक ये बुराईयाँ का दिमाग से निकलेगा नहीं।

आज मुझे यहां जिनके परिवार में बेटी पैदा हुई है, उन माताओं से उन बच्चियों से मिलने का सौभाग्य मिला। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। मैंने उनको पूछा कि क्या आपको पता है, आपको किसी ने बताया कि आज जब पैदा हुई थीं तब मिठाई बांटी गई थी? उन्होंने कहा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हमने बेटी पैदा हुई तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी और एक जश्न मनाया था।

हमें ये स्थिति बदलनी है और ये बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम जो सरकार द्वारा हो रहे हैं, उसी के तहत आज इस योजना को पूरे देश में हम विस्तार कर रहे हैं।

दूसरा- आज कार्यक्रम एक लॉन्च हो रहा है-पोषण मिशन का, राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब किसी को भी पीएम को गाली देनी है, पीएम की आलोचना करनी है, पीएम की बुराई करनी है तो मेरी उनको प्रार्थना है कि जितनी बार आप पीएम की बुराई करें, पीएम की आलोचना करें, अच्छा कहें, बुरा कहें, भला करें न करें, लेकिन जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए; तो आपको नरेन्द्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए। देखिए कैसे एक दम से घर-घर फैल जाता है।

और हमारे यहां बेटा हो या बेटी- उसका शरीर का जो विकास होना चाहिए, वो रुक जाता है। कभी जन्म के समय ही बहुत कम वजन का बच्चा पैदा होता है और उसमें भी अज्ञानता बहुत बड़ा रोल करती है। हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। और फिर भी मैं कहता हूं ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं हैं। ये तब होता है जब जन-आंदोलन बनता है। लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महात्म्य की ओर देखा जाता है।

कुपोषण के खिलाफ पहले काम नहीं हुए, ऐसा नहीं है। हर सरकार में कोई न कोई योजनाएं बनी हैं। लेकिन देखा ये गया है कि ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि अगर जितना कैलोरी चाहिए, उतना अगर उसके पेट में जाएगा तो फिर कुपोषण से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अनुभव कहता है कि सिर्फ

खाना ठीक हो जाए, इतने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये पूरा eco system correct करना पड़ता है। खाना अच्छा भी मिल जाए लेकिन अगर वहां पानी खराब है, कितना ही खाते जाओ- वो कुपोषण की स्थिति में फर्क नहीं आता है।

बहुत कम लोगों को मालूम होगा बाल-विवाह-Child Marriage- ये भी कुपोषित बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। छोटी आयु में शादी हो जाना, बच्चे हो जाना- न मां के शरीर का विकास हुआ है, न आने वाले बच्चे के शरीर पर कोई भरोसा कर सकता है। और इसलिए सब-जीवन से जुड़े जितने पहलू हैं- अगर बीमार हैं तो समय पर दवाई, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पीने का सौभाग्य, otherwise हमारे यहां तो पूरी मान्यता रही है, पुराने लोग तो कहते हैं- नहीं, नहीं जन्म के तुरंत बाद मां का दूध मत पिलाओ; गलत है, सच पूछो वो गलती है। जन्म के तुरंत बाद अगर मां का दूध बच्चे को अगर मिलता है तो पोषण के समय में बड़ा होने के समय मुसीबतें कम से कम आती हैं। मां के दूध की ये ताकत होती है, लेकिन हम उसको भी नकार देते हैं।

इसलिए मां को उसके पूर्ण रूप में, जब उसको स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके महात्म्य को समझते हैं; तो मां- अगर उसकी हम रखवाली करेंगे, तो उसकी गोद से होने वाले बच्चे भी कुपोषण से मुक्त होंगे।

Nutrition की चिंता करना एक काम है। कभी-कभी सरकार के द्वारा vaccination के कई कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन हम उस हेल्थ सेंटर की जितनी सेवाएं हैं- उपलब्ध हैं, बजट है, अफसर है, लोग हैं- लेकिन हम वहां तक जाते नहीं हैं। और उसी का परिणाम है कि वो कोई न कोई बीमारी का शिकार हो जाता है।

आपने अभी जो फिल्म दिखाई- उसमें बताया सिर्फ हाथ धोए बिना खाना, एक अनुमान है कि जो बच्चे मरते हैं- उसमें हाथ न धो करके खाने की आदत, शरीर में जो बीमारियां जाती हैं, उसमें मरने वालों में से 30-40 प्रतिशत होते हैं। अब ये आदत कौन डालेगा कि बच्चों को मां खिलाती है तो मां का भी हाथ धोना होना चाहिए और बच्चा खुद मुंह में कुछ डालता है तो उसका भी हाथ धोना चाहिए, ये कौन सिखाएगा?

ये काम हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना, ये हम सबका दायित्व है। और उसी के तहत इस योजना को एक mission mode में, और बिखरी हुई सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके- चाहे -पानी की समस्या हो या दवाइयों की समस्या हो, चाहे परम्परा की कठिनाइयां हैं। अब बच्चे हैं, हमने देखा होगा कि जो स्कूल में जाते हैं- एक आयु के बाद बच्चों के मन में एक infirmity complex पैदा होता है, किस बात का? अगर उस स्कूल में पांच बच्चों की ऊंचाई ज्यादा है और बाकी नाटे कद के बच्चे हैं, उन सबको लगता है कि मेरी ऊंचाई भी ऐसी होनी चाहिए। फिर वो पेड़ पर कहीं इधर-उधर लटक कर सोचता है कि मेरी ऊंचाई बढ़ी- आप में से सबने ये प्रयोग किया होगा। हर किस को लगता है यार मेरी ऊंचाई बढ़नी चाहिए। लेकिन हम वैज्ञानिक तरीकों से इन चीजों पर काम नहीं करते।

आज हमारे देश में उम्र के हिसाब से ऊंचाई होनी चाहिए, उसमें काफी कमी नजर आती है। हमारे बच्चे तंदुरुस्त हों, वजन हो, ऊंचाई हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दे करके एक holistic approach के साथ 2022, जब हमारी आजादी के 75 साल होंगे, तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सकें दुनिया के सामने कि हमने achieve कर दिया है और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते-खेलते बच्चे हर पल नजर आएँ, जहां जाएँ वहां नजर आएँ; ये स्थिति हमें पैदा करनी है।

करीब 9 हजार करोड़ रुपये की लागत से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। और निश्चित मानकों के साथ आशा वर्कर हो, village level के volunteers हों, उनके पास टेक्नोलॉजी की मदद रहेगी, regular base पर वो अपना datacollect करेंगे। उसमें कोई उतार-चढ़ाव आता है तो तुरंत ऊपर से intervention होगा। समस्या का समाधान कैसे हो- इन सारी बातों की ओर देखा जाएगा। कभी आठ महीने तक बच्चे का ग्रोथ ठीक हो रहा है, वजन बराबर चल रहा है; बारिश का मौसम आ गया- अचानक बीमारियों का दौर चल पड़ा। एकदम से सैंकड़ों बच्चों की हालत खराब हो जाती है, आपकी आठ महीने की मेहनत एक महीने में नीचे आ जाती है। तो ये एक बड़ा ही challenging काम होता है, लेकिन इस challenging काम को भी हमें पूरा करना है। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो संकल्प किया है, उस संकल्प के द्वारा पूरा होगा।

मिशन इंद्रधनुष के द्वारा टीकाकरण के काम में तेजी आई है और हमारी कोशिश है कि वर्ष के अंत तक 90 प्रतिशत टीकाकरण के काम को हम achieve कर लें।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6000 रुपये की आर्थिक मदद उन माताओं को दे करके उनकी pregnancy के समय उनकी चिंता की जाए, उसके लिए भी सरकार ने और करीब 23लाख महिलाएं स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ करके.... जो लोग वहां हैं, नीचे वाले जो डंडे हैं उनको पकड़ लें, आंधी जरा तेज है, हर कोई उसको पकड़ ले।

उसी प्रकार से घर में लकड़ी का चूल्हा जला करके घर में मां एक दिन में 400 सिगरेट का धुंआ अपने फेफड़ों में ले जाती थी। हमने उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम आरंभ किया है। और मुफ्त में गैस के कनेक्शन पहुंचाने के कारण आज करीब-करीब साढ़े तीन करोड़ परिवारों को उससे मुक्त कराने का काम किया है। आने वाले दिनों में भी विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, आज जिन योजनाओं का आरंभ हुआ है उसको और तेजी से आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे देश को तंदुरुस्त बनाना है। हमारे बच्चे अगर सशक्त हो गए तो हमारे देश का भविष्य भी सशक्त होगा।

इसी संकल्प के साथ आप सब इस जन-आंदोलन में जुड़िए। मैं देशवासियों को आह्वान करता हूं। ये मानवता का काम है, ये आने वाली पीढ़ी का काम है, ये भारत के भविष्य का काम है, आप सब हमारे साथ जुड़िए।

पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए-

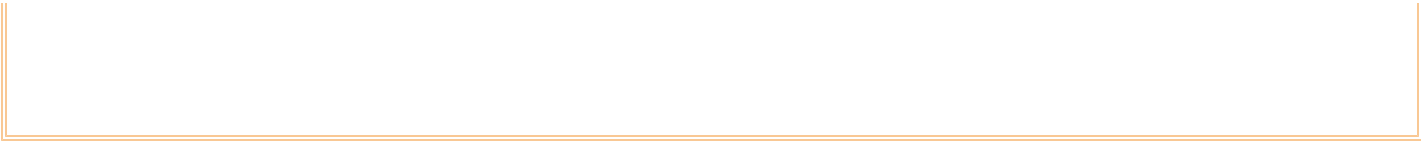
भारत माता की - जय

भारत माता की - जय

भारत माता की - जय

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/शाहबाज हसीबी/बाल्मीकि महतो/ निर्मल शर्मा



प्रधानमंत्री कार्यालय

बीजापुर , छत्तीसगढ़ में हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उद्घाटन के साथ ही आयुष्मान भारत के शुभारम्भ पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 14 APR 2018 8:32PM by PIB Delhi

भारत माता की - जय

भारत माता की – जय

मैं कहूंगा बाबा साहेब आम्बेडकर – आप सब बोलेंगे दो बार- अमर रहे, अमर रहे।

बाबा साहेब आम्बेडकर – अमर रहे, अमर रहे।

बाबा साहेब आम्बेडकर – अमर रहे, अमर रहे।

बाबा साहेब आम्बेडकर – अमर रहे, अमर रहे।

बस्तर आऊर बीजापुर जो आराध्य देवी मां दंतेश्वरी, भैरम गढ़ चो बाबा भैरम देव, बीजापुर चो चिकटराज आउर कोदाई माता, भोपाल पट्टम छो भद्रकाली के खूबे खूब जुहार।

सियान, सजन, दादा, दीदी मन के जुहार। लेका-लेकी पढ़तो लिखतो, नोनी बाबू मन के खुबे-खुबे माया।

मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान जे.पी.नड्डा जी, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमण सिंह जी, राष्ट्रीय एसटी कमीशन के चेयरमैन श्री नंद कुमार साई जी, छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य मंत्रीगण और भारी संख्या में यहां पधारे बीजापुर बस्तर के मेरे प्यारे भाइयो और बहनों।

मैं यहां की आदि देवी और देवताओं को सादर नमन करता हूं जिन्होंने बीजापुर ही नहीं बल्कि पूरे बस्तरवासियों को प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। मैं आज बीजापुर की धरती से अमर शहीद गैन्सी को भी याद करना चाहता हूं जो बस्तर की धरती आज से लगभग दो सौ साल पहले अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। ऐसा ही एक नेतृत्व करीब-करीब सौ वर्ष पूर्व महानायक वीर गुन्दाधुर के रूप में भी यहां अवतरित हुआ। गैन्सी हो या गुन्दाधुर, ऐसे अनेक लोकनायक की शौर्य गाथाएं आपके लोकगीतों में पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तार पाती रही हैं।

मैं इस महान धरती के वीर सपूतों और वीर बेटियों को भी नमन करता हूं। इस धरती पर आज भी शौर्य और पराक्रम की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं।

साथियों, स्थानीय चुनौतियों से मुकाबला करते हुए यहां के विकास के लिए प्रयत्नशील यहां के लोगों की सुरक्षा में अपना दिन-रात खपा देने वाले सुरक्षाबलों के अनेक जवानों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की है। ये जवान सड़क बनाने में, मोबाइल के टॉवर लगाने में, गांवों में अस्पताल बनाने में, स्कूल बनाने में, छत्तीसगढ़ के infrastructure को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में जुटे ऐसे अनेक सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। नक्सली माओवादी हमलों में शहीद उन वीर जवानों के लिए स्मारक का निर्माण किया गया है। मैं उन्हें नमन करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं।

साथियों, 14 अप्रैल का आज का दिन देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जन्म-जयंती है। आज के दिन आप सभी के बीच आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिलना, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म-जयंती पर आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए-

जय भीम – जय भीम

जय भीम – जय भीम

जय भीम – जय भीम

आप बस्तर और बीजापुर के आसमान में बाबा साहेब के नाम की गूंज हमें, आप सभी को धन्य कर रही है। बाबा साहेब के नाम की गूंज में जो आशा जुड़ी है, जो आकांक्षा जुड़ी है, उसे भी मैं प्रणाम करता हूं।

साथियों, हमारी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरूआत छत्तीसगढ़ की धरती से की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ भी इसी छत्तीसगढ़ की धरती से किया था। ये योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति को गति देने का काम कर रही हैं।

आज जब मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ आया हूं तो 'आयुष्मान भारत योजना' के पहले चरण और 'ग्राम स्वराज अभियान' की शुरूआत करने के लिए आया हूं। केंद्र सरकार ने बीते चार साल में जो भी योजनाएं गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, महिलाओं और आदिवासियों को ताकत देने के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ इन तबकों तक पहुंचे, इस अभियान से ये सुनिश्चित किया जा रहा है, ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश में आज से 5 मई तक चलाया जाएगा।

मुझे विश्वास है कि बाबा साहेब की जयंती पर आज यहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिन योजनाओं की शुरूआत हुई है वो भी विकास की जीवन धोरण बदलने की एक नए कीर्तिमान बनाने में कामयाब होगी।

भाइयो और बहनों, बाबा साहेब बहुत ही पढ़े-लिखे थे, उच्च शिक्षित थे। अगर वो चाहते तो दुनिया के समृद्ध-समृद्ध देशों में बहुत शानदार ऐशो-आराम की जिंदगी, सुख-चैन की जिंदगी बिता सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विदेश की धरती पर पढ़ाई करके वो वापिस आए और उन्होंने अपना जीवन पिछड़े समाज के लिए, वंचित समुदाय के लिए, दलितों और आदिवासियों के लिए समर्पित कर दिया। वो दलितों को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे। जो सदियों से वंचित थे उन्हें एक सम्माननीय नागरिक की तरह जीने का अवसर दिलाने की उन्होंने जिद ठान ली थी। विकास की दौड़ में जो पीछे छूट गए और जिनको पीछे छोड़ दिया गया, ऐसे समुदायों में आज चेतना जगी है, विकास की भूख जगी है, अधिकार की आकांक्षा पैदा हुई है। ये चेतना बाबा साहेब आम्बेडकर की ही देन है।

प्यारे भाइयो और बहनों, एक गरीब मां का बेटा, अति पिछड़े समाज से आने वाला ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहेब की ही देन है। साथियों मेरे जैसे लाखों-करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को, उनके aspirations को, अभिलाषा को जगाने में बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान था।

भाइयो और बहनों, आज यहां मेरे सामने बहुत से किसान हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, अलग-अलग दफ्तरों में जाने वाले लोग हैं। कुछ लोग स्वरोजगार करने वाले होंगे, हो सकता है कुछ विद्यार्थी भी हों। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए- जोरों से नहीं देंगे तो चलेगा, मन में जरूर सोचिए- अगर किसी के जीवन में कुछ बेहतर होने की उम्मीद होती है, कुछ बनने का, कुछ पाने का मकसद होता है तो वो दोगुनी डबल मेहनत करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? और जिसको कुछ करना ही नहीं, वो क्या करता है, सोया पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है? जिसके मन में कोई सपना होता है वो ही जागता है कि नहीं जागता है? वो ही मेहनत करता है कि नहीं करता है? आप खुद से सवाल पूछिए।

भाइयो, बहनों, किसान को भरोसा हो कि इस बार अच्छी बारिश होगी और बारिश की शुरूआत अच्छी हो जाए, तो आप मुझे बताइए किसान और जोर से ताकत से मेहनत करता है कि नहीं करता है? बारिश आ रही, बादल घिर गए, वो मेहनत करना शुरू कर देता है कि नहीं कर देता है? क्योंकि उन बादलों के साथ उसके सपने भी जुड़ जाते हैं।

भाइयो और बहनों, आज बाबा साहेब की प्रेरणा से मैं बीजापुर के लोगों में, यहां के प्रशासन में यही एक नया भरोसा जगाने आया हूं, एक नया विश्वास पैदा करने आया हूं, एक नई अभिलाषा जगाने आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि केंद्र की सरकार आपकी आशाओं, आकांक्षाओं, आपकी अभिलाषाएं, aspirations के साथ खड़ी है।

अब मैंने बीजापुर जिले को ही क्यों चुना, इसकी भी एक वजह है। मुझे ठीक से तो याद नहीं लेकिन आपको एक पुराना किस्सा सुनाता हूं। वैसे तो मैं पढ़ने-लिखने में बहुत तेज नहीं था। जब स्कूल में पढ़ता था तो ऐसे ही बड़ा मामूली सा विद्यार्थी था। लेकिन कुछ बच्चे मुझसे भी कमजोर थे। जब स्कूल पूरा हो जाता था, समय पूरा हो जाता था तो कई बार हमारे जो मास्टरजी थे, वो उन बच्चों को रोक लिया करते थे। उन्हें बहुत धैर्य के साथ फिर से पढ़ाते थे, एक-एक बच्चे पर ध्यान देते थे। उन्हें भरोसा दिलाते थे कि तुम पढ़ाई में कमजोर नहीं हो। मैंने देखा था कि ऐसे बच्चे, अगर मास्टरजी उसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, थोड़ा पुरस्कृत कर दें, थोड़ी हिम्मत दे दें; कुछ ही दिनों में बाकी विद्यार्थियों की बराबरी में आ जाते थे और कुछ तो उन्हें पीछे भी छोड़ करके आगे निकल करके नंबर ले आते थे।

मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा होते देखा होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो कमजोर है, जो पीछे है; अगर उसे थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दिया जाए तो वो दूसरों से आगे निकलने की ताकत ज्यादा रखता है और बड़ी जोर से निकल भी जाता है। आज मेरे बीजापुर आने की यही वजह है कि उस पर भी कमजोर होने का, पिछड़ा जिला होने का लेबल जो लगा दिया गया है और देश में बीजापुर ऐसा अकेला जिला नहीं है। सौ से ज्यादा जिलों में यही स्थिति है। स्वतंत्रता के बाद इतने वर्षों में भी ये जिले पिछड़े बने रहे। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बाबा साहेब के संविधान ने इतने अवसर दिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया लेकिन फिर भी सौ से अधिक जिले विकास की दौड़ में पीछे क्यों छूट गए?

भाइयो और बहनों, क्या इन जिलों में रहने वाली माताओं को ये अधिकार नहीं था कि उनके बच्चे भी स्वस्थ हों? उनमें भी खून की कमी न हो? उनकी भी ऊंचाई ठीक से बढ़े? क्या इन जिलों के लोगों ने अपने देश से ये आशा नहीं रखी थी कि उन्हें भी विकास में साझीदार बनाया जाए? क्या इन क्षेत्र के बच्चों को, बेटियों को पढ़ाई का, अपने कौशल के विकास का अधिकार नहीं था क्या? क्या उनको उम्मीद नहीं थी क्या? अस्पताल, स्कूल, सड़कें, पीने का शुद्ध पानी, आजादी के बाद भी देश में बहुत कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई कमी रह गई कि देश के सौ से ज्यादा जिले आज भी सामान्य से भी पीछे हैं। ये भी बहुत हैरत की बात है कि ये जो पिछड़े जिले कहे जाते हैं उनमें प्राकृतिक संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। आपके बीजापुर जिले के पास क्या नहीं है? सब कुछ है।

भाइयो और बहनों, मैं आज इसलिए बीजापुर आया हूं ताकि आपको बता सकूं, आपको भरोसा दिला सकूं कि आप जो पीछे थे, जिनके नाम के साथ पिछड़ा जिला होने का लेबल लगा दिया गया है, उनमें अब नए सिरे से, नई सोच के साथ, बड़े पैमाने पर काम होने जा रहा है। और मैं बीजापुर को एक और भी बधाई देना चाहता हूं कि मैंने जनवरी में ये सौ-सवा सौ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाया था और उनको मैंने कहा था कि आज जहां है, अगर तीन महीने में जो तेज गति से आगे बढ़ेगा, मैं 14 अप्रैल को उस जिले में आऊंगा। मैं बीजापुर जिले के अधिकारियों की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उन्होंने तीन महीने में ये जो सौ से अधिक पीछे थे, उसमें सुधारने में नंबर एक कर दिया और एक प्रकार से उन्होंने जो करके दिखाया है उसे मैं सलाम करने आया हूं, उसे मैं नमन करने आया हूं और यहां से देख करके एक नई प्रेरणा भी लेने आया हूं ताकि देश के उन 115 जिलों को पता चले कि अगर बीजापुर 100 दिन में इतनी प्रगति कर सकता है तो 115 जिले भी आने वाले महीनों में बहुत तेज गति से प्रगति कर सकते हैं।

मैं इन 115 aspirational डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ अभिलाषी नहीं, सिर्फ आकांक्षी नहीं, महत्वाकांक्षी जिले कहना चाहता हूँ। अब ये जिले आश्रित नहीं, पिछड़े नहीं रहेंगे। ये परिणाम, पराक्रम और परिवर्तन के नए मॉडल बन करके उभरेंगे, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

भाइयो और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात इतने दावे के साथ कैसे कर सकता हूँ? यहां आने से पहले हमारी सरकार ने बीजापुर समेत 100 से ज्यादा जिलों का अध्ययन करवाया है और कुछ कार्यों को शुरू करके उसके नतीजों को परखा है। तीन महीने का हमारा अनुभव कहता है अगर जिले के सभी लोग, जिले का प्रशासन, जिले के जन-प्रतिनिधि, हर गली-मोहल्ला-गांव अगर इसी अभियान में साथ आ जाए; एक जनआंदोलन की तरह सब इसमें योगदान करें तो वो काम हो सकता है जो पिछले 70 साल में भी आजादी के बाद नहीं हुआ था, वो आज हो सकता है।

साथियों, पुराने रास्ते पर चलते हुए आप कभी भी नई मंजिलों तक नहीं पहुंच सकते। पुराने तौर-तरीकों से दुनिया नहीं बदल सकती। समयानुकूल तौर-तरीके भी बदलने पड़ते हैं। अगर नए लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो नए तरीके से काम करना ही होता है। बीजापुर समेत जो देश के 115 पिछड़े जिले हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार नई approach के साथ काम कर रही है। ये approach क्या है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहां बहुत बड़ी मात्रा में किसान भाई बैठे हैं, बड़ी सरलता से उनको ये समझ आ जाएगा। हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, दालें उगाते हैं। मैं जरा इन किसान भाइयो से पूछना चाहता हूँ- क्या आप सभी फसलों में एक समान ही पानी देते हैं क्या? क्या धान के लिए जितना पानी देते हैं उतना ही मक्के के लिए देते हैं? उतना ही सब्जी के लिए देते हैं? इतना ही आप चावल के लिए देते हैं? आपका जवाब होगा ना, नहीं देते हैं। चावल के लिए ज्यादा देते हैं, इस फसल के लिए इतना देते हैं, इस फसल के लिए इतना देते हैं। अलग-अलग फसल के लिए आप अलग-अलग प्रकार से काम करते हैं कि नहीं करते हैं? सामान्य किसान भी ऐसा करता है। इसी तरह जब अलग-अलग आवश्यकताएं हैं तो उनकी दिक्कतें भी, उनकी कमजोरियां भी, उनकी चुनौतियां भी अलग-अलग ही होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हर जिले को उसके अपने हिसाब से आगे की रणनीति बनानी होगी, विकास का अपना खुद का प्लान तैयार करना होगा। स्थानीय संसाधनों के आधार पर करना होगा।

आपसे बात करके यहां का प्रशासन आपकी एक-एक आवश्यकताओं के बारे में, उनकी पूर्ति कैसे हो, इस बारे में योजना बनाएगा। बहुत छोटे-छोटे कदम आपको विकास की बड़ी दौड़ में अक्वल नंबर पर ले जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र और राज्य की टीम, गांव, ब्लॉक के लोग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे।

साथियों, आज यहां इस मंच से देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली, देश में सामाजिक असंतुलन खत्म करने वाली एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ हुआ है। 'आयुष्मान भारत' इस योजना के पहले चरण को आज 14 अप्रैल, आम्बेडकर जी की जयंती के दिन इसी धरती से, छत्तीसगढ़ की धरती से, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की धरती से, आज उसका प्रारंभ किया जा रहा है। उसके पहले चरण का प्रारंभ हुआ है। और पहले चरण में देश के प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत देश की हर बड़ी पंचायत में यानी लगभग डेढ़ लाख जगह पर, हिन्दुस्तान के डेढ़ लाख गांवों में sub-centre और primary health centers को Health and Wellness Centres के रूप में विकसित किया जाएगा। और मैं तो नौजवानों से कहता हूँ कि mygov.in पर जा करके ये Health and Wellness Centre है। उसका हमारी सामान्य भाषा में क्या शब्दोपयोग करना चाहिए, मुझे सुझाव दीजिए, मैं जरूर उसका अध्ययन करूंगा। आज अभी तो नाम popular हुआ है Health and Wellness Centre लेकिन आगे चलकर गांव का गरीब एवं अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सके, पहचान सके, ऐसा शब्द इस योजना को मैं देना चाहता हूँ, लेकिन वो भी आपके सुझावों से देना चाहता हूँ। गांव के लोगों के सुझाव से देना चाहता हूँ।

सरकार का लक्ष्य इस काम को 2022 तक पूरा करने का है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम सिर पर लिया है। यानी जब देश आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा होगा, तब तक देशभर में Health and Wellness Centre का एक जाल बिछा जा चुका होगा। इसमें भी उन 115 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी विकास

की रेस में ओरों से थोड़ा पीछे हैं।

भाइयो और बहनों, इन वेलनेस सेंटरों की जरूरत क्यों है? इसे मैं विस्तार से आपको समझाना चाहता हूं। जब हम Health and Wellness Centre की बात करते हैं तब हमारा प्रयास सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है। हमारे देश में ब्लडप्रेसर हो, डायबिटीज, के मरीज बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हृदय रोग की बीमारी से जुड़ी समस्या, मधुमेह, डायबिटीज, सांस लेने में परेशानी, कैंसर; ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते 60 प्रतिशत लोगों की दुखद मौत इन्हीं चार बीमारियों के रहते होती है। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जिनको समय रहते अगर पकड़ लिया जाए तो इनको बढ़ने से रोका जा सकता है।

अब Health and Wellness Centres को भी ये नई व्यवस्था खड़ी की जा रही है। उसके माध्यम से तमाम तरह की जांच भी मुफ्त में करने का भरसक प्रयास किया जाएगा।

साथियों, सही समय पर होने वाली जांच कैसे फायदेमंद होती है, इसका भी उदाहरण मैं आपको दूंगा। मान लीजिए 35 साल का कोई युवा जांच कराए और उसे ब्लड प्रेशर की समस्या का पता चल जाए तो भविष्य में होने वाली कई गंभीर बीमारियों से पहले ही वो बच सकता है। अगर पहले से जांच कराकर, सही समय पर दवाई लेकर, योग, व्यायाम या फिर कुछ आवश्यक परहेज ; बड़े खर्चे और रिस्क दोनों से बचा सकती है।

मैं आज जब Wellness Centre का उद्घाटन कर रहा था तो 30-35 साल की एक बहन वहां पर मिली, उसको पता ही नहीं था, उसको डायबिटीज है। डॉक्टर को आ करके कहा कि मुझे बहुत पानी पीने की तलब लगती है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे थकान महसूस होती है; जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसकी डायबिटीज बहुत खराब हालत में है। 30-32 साल की बहन, उसे पता ही नहीं था कि उसको क्या बीमारी है। लेकिन आज Wellness Centre में आई तो उसको पता चल गया और अब उसको पता चलेगा क्या खाना, कैसे खाना, कैसे रहना। वो उसको कंट्रोल करके बाकी बीमारियों से अपने-आपको बचा पाएगी। इलाज से ज्यादा अहमियत को जोर देने वाली इसी सोच को ये Health and Wellness Centres गांव-गांव पहुंचाने वाला है।

ये Health and Wellness Centres एक प्रकार से गरीबों के फैमिली डॉक्टर की तरह काम करेगा। पुराने जमाने में मध्यमवर्गीय और बड़े परिवारों में फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। अब ये Wellness Centre ऐसा हो जाएगा जैसे वो जैसे वो आपके परिवार का ही एक्सटेंशन है, वो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा।

साथियों, आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है बल्कि ये जनभागीदारी का एक आह्वान भी है ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें। आज तो आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई है। अब अगला लक्ष्य लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों को गंभीर बीमारी के दौरान पांच लाख रुपये तक की, एक वर्ष में पांच लाख, आर्थिक सुरक्षा देने का है। इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है।

भाइयो और बहनों, परिवर्तन तब आता है जब प्रेरणा के साथ संसाधनों का भी सही उपयोग किया जाए। आज यहां मंच पर हमने अभिलाषी बीजापुर के साथ ही अभिलाषी छत्तीसगढ़ की भी बात की है। अटल जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए बीते 14 वर्षों में राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रमन सिंह जी विकास से जुड़ी योजनाओं को पूरे परिश्रम के साथ, आप लोगों के सहयोग के साथ, आप लोगों के कल्याण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। चार साल पहले केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद उनके इन प्रयासों को, छत्तीसगढ़ के विकास संकल्प को और ताकत मिली है। यहां शासन-प्रशासन, जनता के निकट पहुंचा है। आदिवासी अंचलों के बारे में तेजी से विकास करने और अनेक जनहितकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके छत्तीसगढ़ सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बस्तर और सरगुजा में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज; सहीधर जिलों में स्कूल, कॉलेज तथा स्किल डेवलपमेंट की शानदार संस्थाएं संचालित होना इन आंचलों में नई क्रांति का माध्यम बन गया है।

मुझे यहां एक बेटी मिली लक्ष्मी करके, उसने ड्रोन बनाया है। कोई कल्पना कर सकता है कि छत्तीसगढ़-रीवा के आदिवासी क्षेत्र में लक्ष्मी नाम की दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ड्रोन बनाए। वो मुझे कह रही थी मैं 50 मीटर तक उड़ाती हूं और आगे-पीछे भी उसको ले जाती हूं। मुझे खुशी हुई।

आपने सुना होगा, हम जानते हैं नगरनार के स्टील प्लांट का काम पूरा हो रहा है, और स्टील प्लांट का काम, जल्दी ही वो प्लांट भी शुरू हो जाएगा। आज जब बस्तर के युवाओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज ही नहीं, यूपीएससी और पीएससी में सफल होते देख रहा हूं तो मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है कि आपका राज्य सही दिशा में प्रगति कर रहा है। जबसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से स्वास्थ्य सेवा में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। कभी राज्य में दो मेडिकल कॉलेज यहां हुआ करते थे, आज मुझे बताया गया कि दस मेडिकल कॉलेज यहां हो चुके हैं। इससे मेडिकल सीटों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बीजापुर और आसपास के क्षेत्रों में अब स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। जिलों के अस्पतालों में लेकर हाट-बाजारों तक अब बड़े-बड़े विशेषज्ञ अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनके सेवा भाव की हृदय से प्रशंसा करता हूं। और मुझे यहां कई डॉक्टर मिले; कोई तमिलनाडु से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं और अपना पूरा समय इन जंगलों में खपा रहे हैं। जिस देश के पास ऐसे नौजवान डॉक्टरों की फौज हो, वहां मेरा गरीब अब बीमारी से पीड़ा को भोगने के लिए मजबूर नहीं होगा, ये मेरा विश्वास मजबूत हुआ है।

अब से कुछ समय पहले मुझे यहां के जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ करने का भी अवसर मिला है। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत अब देश के 500 से ज्यादा अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ लगभग ढाई लाख मरीज उठा चुके हैं जिन्होंने लगभग 25 लाख डायलिसिस के सेशन किए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे में सबसे नीचे दिखने वाला सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में विकास का जो ताना-बाना बुना गया है, वो मैं प्रशंसा के पात्र हूँ, मैं यहां की सरकार को बधाई देता हूँ।

छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर और तेजी से आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। पहला प्रयास इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास का है और दूसरा जो नौजवान भटके हुए हैं, उनको हर संभव तरीके से विकास की मुख्य धारा से वापस जोड़ने का है। पिछले चार वर्षों में छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर में विकास की अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की गई हैं।

बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में चार सौ किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का जाल बिछाया गया है। जिन गांवों तक पहले जीप तक नहीं पहुंच पाती थी, वो अब नियमित चलने वाली बसों से जुड़ गए हैं।

सौभाग्य योजना के तहत बस्तर के हर घर में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। घरों में पहुंचा उजाला किसान, छात्र, दुकानदार, छोटे उद्यमी, हर किसी की जिंदगी में उजाला ले करके आएगा। बस्तर में हजारों की संख्या में सोलर पंप का वितरण भी किया जा रहा है। ये सोलर पंप किसानों की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। आज इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्कूल, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी राशन की दुकानें, बैंकों की शाखाएं, एटीएम; से सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोबाइल टॉवर लगाए जा रहे हैं। बस्तर अब रेल के माध्यम से रायपुर से जुड़ रहा है।

आज एक रेल सेक्शन का काम शुरू किया गया है। दो वर्ष के भीतर ये जगदलपुर तक पहुंच जाएगा। इस साल के अंत तक जगदलपुर में एक नया स्टील प्लांट भी काम करने लगेगा। इससे बस्तर के भी युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

जगदलपुर में नया एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है और ये अगले कुछ महीनों में काम भी शुरू कर देगा। हवाई जहाज से connectivity इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

साथियो, बस्तर बदल रहा है। बीते दशकों में बस्तर के साथ जिस प्रकार की पहचान जोड़ दी गई थी, वो भी बदल रही है। भविष्य में बस्तर की नई पहचान एक economic hub के तौर पर होने वाली है, पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर होने वाली है। ट्रांसपोर्ट के एक बड़े केंद्र के तौर पर होने वाली है। यहां से रायपुर ही नहीं, हैदराबाद, नागपुर और विशाखापट्टनम तक connectivity हो जाएगी।

न्यू इंडिया के साथ-साथ न्यू बस्तर यहां के लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। दसों दशकों से उनके जीवन में जो अंधेरा था, उस अंधेरे से उन्हें बाहर निकालेगा। नया बस्तर, नई उम्मीदों का बस्तर होगा, नई आकांक्षाओं का बस्तर होगा, नई अभिलाषा का बस्तर होगा। अब ये कहा जा सकता है कि सूरज भले ही पूरब से निकलता हो लेकिन वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ में विकास का सूरज दक्षिण से उगेगा, बस्तर से उगेगा। इन क्षेत्रों में उजाला रहेगा तो पूरा प्रदेश प्रकाशमय रहेगा। यहां खुशहाली होगी तो पूरा प्रदेश खुशहाल होगा।

भाइयो और बहनों, सरकारी योजनाओं और सेवाओं को उन तक पहुंचाना, जिन्हें इनकी सही मायनों में आवश्यकता है; ये हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। क्षेत्रीय असंतुलन के पीछे जो बड़े कारण हैं, उनमें ये भी एक है। और मुझे खुशी है कि रमण सिंह जी की सरकार इस मामले में संवेदनशील है, अच्छी पहल कर रही है।

थोड़ी देर पहले मुझे जांगला विकास केंद्र जाने का अवसर मिला। इस केंद्र के पीछे की भावना ये है कि क्षेत्र के लोगों के लोगों के लिए एक ही जगह सारी सरकारी सेवाएं मिलें ताकि यहां-वहां भागदौड़ करने में जनता का समय और ऊर्जा नष्ट न हो। चाहे ग्राम पंचायत का कार्यालय हो, सरकारी राशन की दुकान हो, पटवारी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो; ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर देना एक बहुत बड़ी सेवा होगी।

मुझे बताया गया है कि पूरे प्रदेश में ऐसे 14 सेंटर बनाने की योजना सरकार की है। ये विकास केंद्र देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल की तरह काम कर सकते हैं।

साथियों, देश में क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करने का एक तरीका connectivity बढ़ाना है। इसलिए हाइवे हो, रेलवे हो, airway हो या फिर आइवे हो- information way, connectivity पर बल दिया जा रहा है। जिस दौर में फोन और इंटरनेट सबसे बड़ी आवश्यकता बनते जा रहे हैं, उस दौर में अगर किसी क्षेत्र में संचार की अच्छी व्यवस्था न हो तो उसको आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। यही कारण है बस्तर को connect करने के लिए बस्तर नेट परियोजना फेज़ वन का लोकार्पण किया गया है। इस योजना के माध्यम से 6 जिलों में लगभग चार सौ किलोमीटर लंबा optical fiber network बिछाया गया है।

मुझे अभी जांगला के ग्रामीण बीपीओ में भी दिखाया गया कि कैसे इसका इस्तेमाल लोगों की आय को तो बढ़ाएगा ही, उनकी जिंदगी को भी आसान बनाने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ में भारत नेट परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। मुझे बताया गया है कि दस हजार में से चार हजार ग्राम पंचायतें भारत नेट से जोड़ी जा चुकी हैं और बाकी का काम अगले साल तक पूरा करने की तैयारी है।

साथियों, connectivity का एक और माध्यम है रेलवे। आज दल्लीराजहरा भानुप्रताप ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि चालक से लेकर गार्ड तक; ये जो अभी हमने ट्रेन को झंडी दिखाई, इसका पूरा संचालन, ड्राइवर भी, गार्ड भी, सबकी सब महिलाएं चला रही थीं। ये देशवासियों के लिए भी खुशी की खबर होगी कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी जंगलों में ट्रेन चला रही हैं हमारी बेटियां। दल्लीराजहरा से रावगढ़ और रावगढ़ से जगदलपुर रेल लाइन, करीब 23 साल पहले ये इसका प्रस्ताव हुआ था, लेकिन लम्बे समय तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। किसी तरह दल्लीराजहरा से रावगढ़ के बीच काम शुरू तो हुआ लेकिन उसकी प्रगति न के बराबर थी।

हमने इस परियोजना की चिंता की, जिसके कारण बस्तर के उत्तरी क्षेत्र में नई रेल लाइन पहुंच गई है।

आज लगभग 1700 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास भी किया गया है, 1700 करोड़ रुपये। ये सड़कें बीजापुर के अलावा कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और राजनांद गांव में रोड का आधुनिक नेटवर्क तैयार करेंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी 2700 किलोमीटर, दो हजार सात सौ किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बस्तर और सरगुझा जैसे विशाल आदिवासी अंचलों को हवाई सुविधा से जोड़ने के लिए हवाई अड्डों का भी विकास किया जा रहा है। भविष्य में इन क्षेत्रों को भी उड़ान योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

भाइयो और बहनों, बीजापुर में पानी की समस्या दूर करने के लिए पेयजल योजनाओं का भी आज शिलान्यास किया गया है। इसके अतिरिक्त इंद्रावती और मिघालचल नदियों पर दो पुलों के निर्माण का भी काम आज शुरू हुआ है।

भाइयों और बहनों, ये सरकार गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों आदिवासियों की सरकार है। पिछले चार वर्ष के दौरान गरीब और आदिवासियों के कल्याण के लिए किए गए फैसले, नए कानून इस बात के गवाह हैं। इसी कड़ी में आज वन-धन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत वन-धन विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि जंगल के उत्पादों का, वहां के उत्पादों का सही दाम मार्केट में जाते ही मिलना चाहिए। इन केंद्रों के माध्यम से वन से मिलने वाली उपज का प्रचार किया जाएगा, इनमें value addition किया जाएगा, और फिर इसके लिए बाजार खड़ा किया जाएगा।

साथियों, value addition, कितना लाभ होता है, ये मैंने आज यहां देखा। कच्ची इमली जो आज बेचते हैं तो 17-18 रुपये किलो के आसपास बिकती है। लेकिन जब आप इसमें से बीज निकाल देते हैं और इसको किसी अच्छी पैकिंग में बेचते हैं तो यही इमली, 17-18 रुपये वाली इमली 50-60 रुपये किलो तक पहुंच जाती है; यानी तीन गुना कीमत बढ़ जाती है।

भाइयो और बहनों, आज हमने यहां वन-धन योजना का आरंभ किया। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, वन-धन योजना और तीसरा आपने सुना होगा, हमने बजट में कहा है गोवर्धन योजना। अगर गांव में गरीब से गरीब को वन-धन, जन-धन और गोवर्धन, इन तीन योजना मुहैया करा दें, गांव का अर्थ-जीवन बदल जाएगा, ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं।

आदिवासियों के हितों को देखते हुए वन-अधिकार कानून को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। हाल ही में एक और बड़ा फैसला इस सरकार ने लिया है, ये है बांस से जुड़े पुराने कानून में बदलाव। साथियों, वर्षों पुराना ये कानून था, जिसके तहत बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। और पेड़ की श्रेणी में रखने के कारण बांस को काटने, बांस को कहीं ले आने में-जाने में कई कानूनी बाधाएं आती थीं, दिक्कतें होती थीं।

लेकिन अब केंद्र सरकार ने वन कानून में बदलाव करके बांस, जिसको अब तक पेड़ की लिस्ट में रखा गया था, हमने उसको हटा दिया है और अब आप बांस को बेरोकटोक उसका कारोबार कर सकते हैं, बांस की खेती कर सकते हैं, बांस को बेच सकते हैं।

भाइयों, बहनों, ये जल, ये जमीन और ये जंगल आपके हैं। इन पर आपका अधिकार है। इसी भावना को सरकार ने समझा और 60 साल तक जो एक व्यवस्था चल रही थी, उसमें भी बदलाव किया है। सरकार द्वारा खनन से जुड़े पुराने कानून में परिवर्तन किया गया है। हमने नियम बनाया है कि अब जो भी खनिज निकलेगा उसका एक हिस्सा स्थानीय निवासियों पर खर्च करना आवश्यक होगा। इसके लिए खनन वाले हर जिले में district mineral foundation की स्थापना की गई है।

कानून में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ को करीब-करीब 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त राशि इस नई व्यवस्था के कारण मिली है। सरकार ने ये भी नियम बनाया है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण पर ही खर्च की जाएगी।

भाइयो और बहनों, आदिवासियों की कमाई के साथ-साथ पढ़ाई पर भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। इस साल बजट में कई बड़ी योजनाओं की हमने घोषणा की है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2022 तक देश का वो हर ब्लॉक जहां आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है या फिर कम से कम 20 हजार लोग इस वर्ग के वहां रहते हैं; वहां एक एकलव्य मॉडल रिहायशी residential school बनाया जाएगा।

इसके अलावा सरकार का एक बड़ा कार्य आदिवासी सम्मान, आदिवासी गर्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। देश की स्वतंत्रता में आदिवासियों के योगदान को पहली किसी सरकार द्वारा इस तरह सम्मानित किया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अलग-अलग राज्यों में जहां आदिवासियों ने आजादी

के जंग में बलिदान दिए हैं, आजादी के जंग का इतिहास आदिवासियों के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है; ऐसे स्थानों पर एक उत्तम प्रकार का म्यूजियम बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा; ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि देश की आजादी के लिए मेरे आदिवासी भाइयों, बहनों ने कितने बलिदान दिए हैं, कितनी स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़े हैं।

साथियों, आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक असंतुलन खत्म करने का एक बड़ा माध्यम है बैंक। आज बैंक का कारोबार अनिवार्य रूप से जीवन से जुड़ गया है। आज मुझे यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच का उद्घाटन करने का भी मौका मिला। मुझे बताया गया है कि लोगों को बैंक में अगर काम होता था तो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। ऊपर से बैंकों में स्टाफ की कमी के कारण परेशानी और बढ़ जाती थी। अब इस ब्रांच के खुलने से एक बड़ी सुविधा आपको मिलने वाली है।

हमने पोस्ट ऑफिस को भी अब बैंक के काम के लिए खोल दिया है। तो जहां पोस्ट ऑफिस होगी, वहां भी बैंकिंग का काम होगा। हमने बैंकमित्र गांव में लगाए हैं, वो भी बैंक का कारोबार करते हैं। हमने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बाद बैंकिंग व्यवस्थाओं का spread गांव-गांव तक ले जाने के लिए नई-नई योजनाएं बनाई हैं। भीम एप के द्वारा अपने मोबाइल फोन से पूरा बैंकिंग का लेनदेन का काम हर नागरिक कर सकता है। उसको भी हमें आगे बढ़ाना है।

भाइयों, बहनों, बैंक में खाता होने का कितना लाभ होता है, ये वो लोग भलीभांति जानते हैं जिनके जनधन के खाते खुले हैं। सरकार के लगातार प्रयास की वजह से आज देश में 31 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, जिनको कभी कोई पूछता नहीं था।

आज मुझे एक छत्तीसगढ़ की बेटी सविता साहूजी की ई-रिक्शा पर सवारी का अवसर भी मिला। सविता जी के बारे में मुझे बताया गया कि परिवार में उनको कुछ दिक्कतें रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ई-रिक्शा चला करके अपना गुजारा किया। उन्होंने सदस्य समिति का रास्ता चुना। सरकार ने भी उनकी मदद की और अब वो एक सम्मान भरी जिंदगी जी रही है।

स्वच्छ भारत मिशन हो, स्वस्थ भारत मिशन हो, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो; ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से बेटियों-बहनों को सशक्त करने का काम ये सरकार कर रही है।

उज्ज्वला योजना का भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। अब तक राज्य में 18 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के माध्यम से सरकार का प्रयास भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा से भी जोड़ने का है। इसलिए मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी लोन दिया जा रहा है। मेरी क्षेत्र के नौजवानों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।

मैं आज शासन-प्रशासन से जुड़े अफसरों, कर्मचारियों; उनको भी अपील करता हूं कि वो अपने जिलों को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लें और उसे सिद्ध करके दिखाएं।

भाइयों और बहनों, सरकार सिर्फ योजना बनाने पर ही ध्यान नहीं दे रही बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन तक इन योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, आखिरी व्यक्ति को कैसे लाभ मिले। मेरा आपसे आग्रह है कि देश के अंतिम व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो ये सरकार काम कर रही है, उसको आगे बढ़ाने में बढ़-चढ़ करके हिस्सा लें। आपकी भागीदारी ही इस सरकार की ताकत है और यही ताकत 2022, जब आजादी के 75 साल होंगे, तब न्यू इंडिया बनाने का संकल्प सिद्ध करेगी। बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के सपनों को वो साकार करेगी।

आप सभी यहां आए, इसके लिए आप सभी का एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए नौजवानों को आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म-जयंती पर कहना चाहूंगा- बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, आपके हकों की रक्षा का पूरा खयाल बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में है। आपके हकों की चिंता करना सरकार का दायित्व है। आपको शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी तबाह करने की जरूरत नहीं है। और मैं उन माताओं-पिताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे, आपकी कुछ बेटियां इस राह पर चल पड़ी हैं। लेकिन जरा सोचिए उनके मुखिया कौन हैं। उनका एक भी मुखिया आपके इलाके का नहीं है, आपके बीच में पैदा नहीं हुआ है, वो कहीं बाहर से आए हैं। और वे मरते नहीं हैं, वो जंगलों में छिप करके सुरक्षित रहते हैं और आपके बच्चों को आगे कर-करके उनको मरवा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के पीछे आप अपने बच्चों को बर्बाद करेंगे? ये आपके राज्य से भी नहीं आते, ये बाहर से आते हैं। उनके सरनेम देखोगे, उनके नाम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो कौन हैं और कहां से आए हैं। क्यों अपने बच्चों को मारने का अधिकार उनके हाथ में दे दिया जाए?

और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विकास के रास्ते पर जाना है। आपके बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले, आपकी फसलों का पूरा दाम मिले, आपको सम्मान की जिंदगी मिले। दवाई हो, पढ़ाई हो, कमाई हो; ये सारी आपकी आवश्यकताएं पूरी हों, और इसके लिए इन कामों को करने में सुरक्षाबल के जवान, आपके यहां स्कूल चालू रहे, टीचर आ सके, इसलिए वो जिंदगी खपा देता है। आपके यहां रास्ता बने, सड़क बने, इसलिए वो बलिदान मोल लेता है। आपके यहां टेलीफोन का टॉवर लग जाए, इसलिए वो गोलियां खाता है। विकास के लिए वो मुट्ठी में जिंदगी ले करके आपकी सेवा करने के लिए आया है।

आइए मेरे भाइयो, बहनों, विकास के रास्ते पर चल पड़ें। देश को नई ऊंचाइयों पर ले चलें। 115 अभिलाषी जिले हैं, महत्वाकांक्षी जिले हैं, आकांक्षा वाले जिले हैं, उनमें एक बदलाव लाने का संकल्प करें। आयुष्मान भारत का सपना पूरी मेहनत के साथ हम पूरा करें।

इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबको इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए, इतना बड़ा शानदार-जानदार कार्यक्रम इन जंगलों में करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

जय भीम – जय भीम, जय हिंद।

अतुल तिवारी/ कंचन पतियाल / निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1529157) आगंतुक पटल : 1450

प्रधानमंत्री कार्यालय

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के शुभारंभ पर मण्डला, म.प्र. में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूलपाठ

प्रविष्टि तिथि: 24 APR 2018 7:46PM by PIB Delhi

मंच पर विराजमान मध्यप्रदेश के गर्वनर श्रीमती आनंदी बेन पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला, राज्य सरकार के मंत्री गोपाल जी, ओमप्रकाश जी, संजय जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान फगुन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती संपत्तिया वी.के.जी, और अब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं और हमारे जबलपुर के सांसद हैं; श्रीमान राकेश सिंह जी, मंडला जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी जी और आज बड़े गर्व के साथ एक और परिचय भी करवाना चाहता हूँ- हमारे बीच बैठे हैं त्रिपुरा के उप-मुख्यमंत्री। पिछले दिनों त्रिपुरा के चुनाव ने एक ऐतिहासिक काम किया। वहां की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई।

त्रिपुरा में ज्यादातर जनजातीय समुदाय रहता है। आपको जैसे यहां गोंड परम्परा का इतिहास है वैसे ही त्रिपुरा में आदि जाति के लोगों का, जनजातीय समुदायों का, वहां के राज-शासन का एक बहुत बड़ा लम्बा इतिहास है। और मुझे खुशी है कि आज उस त्रिपुरा के नव-निर्वाचित उप-मुख्यमंत्री श्रीमान जिशूदेव वर्मा जी मेरे बीच में हैं और वे त्रिपुरा के उस जनजातीय समुदाय से आते हैं और उस राजपरिवार से आते हैं जिन्होंने अंग्रेज सल्तनत के सामने लोहा लिया था; आज उनका यहां मध्यप्रदेश की धरती पर स्वागत करने में मुझे गर्व हो रहा है।

भाइयो, बहनों, हम सब आज मां नर्मदा की गोद में इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले करीब-करीब 1300 किलोमीटर लम्बे पट वाली मां नर्मदा, यहां से शुरू होकर गुजरात में समुद्री तट तक जाने वाली मां नर्मदा, हमारे करोड़ों लोगों की जिंदगी को संभालने-संवारने वाली मां नर्मदा; हमारा पशुपालन हो, हमारी कृषि हो, हमारा ग्रामीण जीवन हो; सदियों से मां नर्मदा ने हमें नई जिंदगी देने का काम किया है। मैं उस मां नर्मदा को प्रणाम करता हूँ।

आज मेरा सौभाग्य है, मुझे इस क्षेत्र में पहले भी आने का सौभाग्य मिलता रहा है। रानी दुर्गावती, पराक्रम की गाथाएं, त्याग और बलिदान की गाथाएं हम सबको प्रेरणा देती रही हैं। और ये हमारे देश की विशेषता रही है चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी अवन्तीबाई हो; समाज के लिए संघर्ष करते रहना, विदेशी सल्तनत के सामने कभी झुकना नहीं, जीना तो शान से और मरना तो संकल्प को ले करके मरना, ये परम्परा के साथ आज हम इस धरती पर हमारी आदिजाति का एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं।

लेकिन साथ-साथ आज पंचायत दिवस भी है। पूज्य बापू के सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत की पहचान भारत के गांवों से है, इस संकल्प को बार-बार दोहराया था। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना दी थी। महात्मा गांधी ने ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, ये मार्ग हमें प्रशस्त करने के लिए प्रेरित किया था। और आज पंचायत राज दिवस पर मैं देश की करीब दो लाख चालीस हजार पंचायतों को, इन पंचायतों में रहने वाले कोटि-कोटि मेरे भारतवासियों को, इन पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के रूप में बैठे हुए 30 लाख से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को और उसमें भी एक-तिहाई से ज्यादा हमारी माताएं-बहनें, जो आज ग्रामीण जीवन का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसे सबको आज पंचायती राज दिवस पर प्रणाम करता हूं, बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके अपने गांव के विकास के लिए, आपके अपने गांव के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, आपके अपने गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आप जो भी संकल्प करेंगे उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम भी, भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेगी। आपके सपनों के साथ हमारे सपने भी जुड़ेंगे, और हम सबके सपने मिल करके सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों को हम सिद्ध करके रहेंगे। इसी एक भावना के आज पंचायत राज दिवस पर गांव के लिए कुछ करने का संकल्प करें।

पुराने जमाने में कभी-कभी हम जब यहां भी मंडला में आते हैं तो उस किले की पहचान होती है, उस राजपरिवार की व्यवस्था की पहचान होती है और हम सब बड़ा सीना तान कर कहते हैं कि सदियों पहले गोंड राजाओं ने कितना बड़ा काम किया था, कैसी बड़ी व्यवस्थाएं की थीं। उस समय राज-व्यवस्थाएं थीं, राज-परम्पराएं थी और राज-परम्पराओं से जुड़े हुए लोग अपने इलाके के नागरिकों की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करते थे जिसको आज सदियों के बाद भी हम इतिहास के माध्यम से स्मरण करते हैं, गर्व करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं। उस जमाने में जो व्यवस्था जी उस व्यवस्था के तहत ये होता था।

अब लोकतंत्र है, एक निश्चित अवधि के लिए गांव के लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है, गांव के लोगों ने हम पर भरोसा रखा है। ऐसा कौन पंचायत का प्रधान होगा, ऐसा कौन पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा जिसके दिल में ये इच्छा न हो कि पांच साल जो मुझे मिले हैं, मैं पांच साल में मेरे गांव के लिए ये 5 अच्छे काम, 10 अच्छे काम, 15 अच्छे काम मेरे कार्यकाल में करके ही रहूंगा। ये संकल्प, और तब जा करके 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद, जब आप बुढ़ापे से गुजरते होंगे, घर में पोते-पोतियों को ले करके कभी रास्ते में निकलेंगे, तो आप भी अपने पोते-पोतियों को बताएं कि 25 साल पहले मैं पंचायत का प्रधान था, 25 साल पहले मैं पंचायत में चुन करके आया था और देखो मेरे समय में मैंने ये तालाब का काम किया था, मेरे समय में ये स्कूल में मैंने ये पेड़ लगाया था, मेरे समय में मैंने ये तालाब में काम किया था, मेरे समय में मैंने ये कुआ खूदवाया था, गांव को पानी मिला था। आप भी जरूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जब अपने पोते-पोतियों

को आप कहें कि जनता ने आपको चुन करके बिठाया था और आपने 25 साल, 30 साल पहले ये काम किया था और जिसका हमें संतोष है। कौन पंचायत का व्यक्ति हो जिसके दिल में ये इच्छा नहीं होगी?

मैं आपके हृदय में वो इच्छा को प्रबल करना चाहता हूँ। आपको मजबूत संकल्पों का धनी बनाना चाहता हूँ। अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा और उसके लिए जो पांच साल मिलते हैं, वे पांच साल पल-पल जनता-जनार्दन के लिए खपा देने का अगर प्रण ले करके चलें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की कोई चुनौती नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, जिसको हम परास्त करके हम हमारे गांव की जिंदगी को बदल न सकें।

कभी-कभी गांव के विकास की बात आती है तो ज्यादातर लोग बजट की बातें करते हैं। कोई एक जमाना था जब बजट के कारण शायद मुसीबतें रही हों, लेकिन आज बजट की चिंता कम है, आज चिंता है बजट का, पैसों का सही उपयोग कैसे हो? सही समय पर कैसे हो? सही काम के लिए कैसे हो? सही लोगों के लिए कैसे हो? और जो हो इसमें ईमानदारी भी हो, पारदर्शिता भी हो और गांव में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये काम हुआ, इतने पैसों से हुआ और ये गांव को हिसाब में दे रहा हूँ। ये आदत, समस्या पैसों की कभी नहीं है, लेकिन समस्या कभी प्राथमिकता की होती है।

आप मुझे बताइए, गांव में स्कूल है, स्कूल का अच्छा मकान है, गांव में मास्टरजी को नियुक्त किया गया है, मास्टरजी को तनख्वाह रेग्युलर मिल रही है, स्कूल के समय स्कूल खुल रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी मेरे गांव के पांच-पच्चीस बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, खेत में जा करके छिप जाते हैं, पेड़ पर जा करके बैठ जाते हैं, और मेरे गांव के 5-25 बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, मुझे बताइए ये 5-25 बच्चे अनपढ़ रह गए, क्या बजट समस्या थी? जी नहीं, मास्टर की समस्या थी? जी नहीं। हम गांव के लोगों ने हमारे गांववासियों को ये जो बात समझानी चाहिए कि भई स्कूल है, मास्टरजी हैं, सरकार फीस देती है, सरकार यूनिफार्म देती है, सरकार मध्याह्न भोजन देती है। आओ, हमारे गांव में एक भी बच्चा स्कूल से छूट नहीं जाएगा। हमारे गांव से एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, क्या ये हम नहीं निर्णय कर सकते?

हमारे माता-पिता अनपढ़ रहे होंगे, उनको शायद वो सौभाग्य नहीं मिला होगा। उस समय की सरकारों के रहते हुए वो पढ़ नहीं पाए होंगे लेकिन हम अगर पंचायत में चुन करके आए हैं, राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, बच्चों की शिक्षा के लिए आग्रही है, बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष आग्रही है; तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि जनप्रतिनिधि के नाते पांच साल में ऐसा काम करूं कि स्कूल जाने की उम्र का एक भी बच्चा अनपढ़ न रहे। आप देखिए वो बच्चा जब बड़ा होगा, अच्छी पढ़ाई करे आगे निकलेगा; वो बच्चा बड़ा हो करके कहेगा कि मैं तो गरीब मां का बेटा था, कभी मां के साथ खेत में काम करने जाता था, लेकिन मेरे गांव के प्रधानजी थे, वो खेत में से मुझे पकड़ कर ले गए थे और मुझे कहा- बेटे अभी तेरी उम्र खेत में काम करने की नहीं है, चल स्कूल चल, पढ़ाई कर, और प्रधानजी मुझे

ले गए थे। उसी की बदौलत आज मैं डॉक्टर बन गया, आज मैं इंजीनियर बन गया, आज मैं IAS अफसर बन गया, मेरे परिवार की जिंदगी बदल गई। एक प्रधानजी के कारण एक जिंदगी भी बदल जाती है तो पूरा हिंदुस्तान बदलने सही दिशा में चल पड़ता है।

और इसलिए मेरे प्यारे सभी प्रतिनिधि, ये पंचायत राज दिवस, ये हमारे संकल्प का दिवस होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आज के जमाने में आरोग्य के क्षेत्र में इतने अच्छे संशोधन हुए हैं। अगर पोलियो की खुराक सही समय पर बच्चों को पिला दी जाए तो हमारे गांव में बच्चे को पोलियो होने की संभावना नहीं है, बच जाता है। आप मुझे बताइए आज भी आपके गांव में कोई 40 साल का, कोई 50 साल का व्यक्ति पोलियो के कारण परेशानी की जिंदगी जीता होगा, दिव्यांग अवस्था में आप देखते होंगे, आपके मन में पीड़ा होती होगी कि नहीं होती होगी? आपको लगता होगा कि नहीं लगता होगा, अरे भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया बेचारा चल भी नहीं पाता है। आपके मन में जरूर भाव उठता होगा।

मेरे भाइयो, बहनों, 40-50 साल की उम्र के उस व्यक्ति को शायद वो सौभाग्य मिला नहीं। लेकिन आज, आज पोलियो का खुराक, आपके गांव के किसी भी बच्चे को अपाहिज नहीं होने देता है, दिव्यांग नहीं बनने देता है, उसको पोलियो की बीमारी नहीं आ सकती है। क्या पोलिया का खुराक, इसके बजट लगेगा क्या? डॉक्टर आते हैं, सरकार आती है, पैसे खर्च किए जाते हैं, पोलियो के खुराक की तारीख की टीवी में, अखबार में लगातार एलान होता है। क्या मैं पंचायत में से चुना हुआ व्यक्ति, मैं मेरे गांव में पोलियो के खुराक के अंदर कभी भी कोताही नहीं बरतूं, क्या ये निर्णय मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्या ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं?

लेकिन कभी-कभी जनप्रतिनिधियों को लगता है ये काम तो सरकारी बाबुओं का है, हमारा काम नहीं है। जी नहीं, मेरे प्यारे भाइयो, बहनों, हम जनता के सेवक हैं, हम सरकार के सेवक नहीं हैं। हम जनप्रतिनिधि जनता की सुखाकारी के लिए आते हैं और इसलिए हमारी शक्ति, हमारा समय अगर उसी काम के लिए लगता है तो हम अपने गांव की जिंदगी बदल सकते हैं।

आप मुझे बताइए- मैं छोटी-छोटी बातें इसलिए बताता हूं कि कभी-कभी बड़ी बातें करने के लिए तो बहुत सही जगह होती हैं और बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी बातें बताते भी रहते हैं। लेकिन हमें अपने गांव में छोटी-छोटी बातों से भी परिवर्तन आता है।

हमें मालूम है हमारे गांव का किसान- क्या उसको ये पता है कि अगर जिस खेत से उसका पेट भरता है, जिस खेत से वो समाज का पेट भरता है, अगर उस मिट्टी की सेहत अच्छी नहीं होगी, तो कभी न कभी वो धरती माता रूठ जाएगी कि नहीं जाएगी? धरती माता आज जितनी फसल देती है, वो देना बंद करेगी कि नहीं करेगी? हम भी भूखे मरेंगे और भी भूखे मरेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी गरीबी में गुजारा करने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्या कभी सोचा है हम कभी गांव के लोगों को बिठाएं, बिठा करके तय करें कि भाई बताओ, हम जल्दी-जल्दी फसल, ज्यादा-ज्यादा फसल दिखाई दे इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया डालते हैं। बगल वाले ने एक थैला यूरिया डाल दिया तो मैं भी एक थैला डाल देता हूं। बगल वाले

ने दो थैला डाल दिया तो मैं भी दो थैला डाल देता हूँ। बगल वाले ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो मैं भी लाल डिब्बे वाली दवा डाल दूँ और उसके कारण मैं मेरी जमीन को बर्बाद करता हूँ।

क्या गांव के लोग मिल करके तय करें कि हम अगर पहले पूरे गांव में 50 थैला यूरिया आता था, अब हम 40 थैले से चलाएंगे, 40 बैग से चलाएंगे। ये बताइए, गांव के 10 बैग का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? गांव के अंदर यूरिया के कारण जो हमारी मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, हमारी धरती माता बर्बाद हो रही है, उसको बचाने की थोड़ा सी भी हमारी कोई भूमिका बनेगी कि नहीं बनेगी? पैसे भी बचेंगे, धीरे-धीरे फसल भी अच्छी लगने लगेगी। हमारी मां, धरती माता हम पर खुश हो जाएगी, वो भी हमें आशीर्वाद बरसाएगी कि दवाईयां पिला-पिला कर मुझे मार रहा था। अब मेरा बेटा सुधर गया है, अब मैं भी एक धरती मां की तरह से उसका पेट भरने के लिए ज्यादा करूंगी। आप मुझे बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?

मैं आपसे, मेरे आदिवासी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं जनजाति के भाइयों से पूछना चाहता हूँ क्या ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?

आप मुझे बताइए अब सरकार ने एक बड़ा अच्छा नियम बना दिया। मैं मंडला के जंगलों में खड़ा हूँ आज। यहां पर बांस की खेती होती है। एक समय था बांस को हमारे देश में पेड़ माना गया था। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं फाइलें पढ़ रहा हूँ कि इतने साल तक ये बांस को, बाम्बू को पेड़ क्यों माना गया है। और उसके कारण हुआ क्या, मेरा जनजाति का भाई जो जंगलों में रहता है, वो बांस को काट नहीं सकता, बांस को बेच नहीं सकता और अगर कभी जाता है ले करके, और किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने देख लिया तो फिर उसको तो बेचारे को दिन में ही रात के तारे दिखाई देते हैं। ये मुसीबत आती है कि नहीं आती है? परेशानियां होती थीं कि नहीं होती थीं?

सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला ले लिया। सरकार ने अहम फैसला ले लिया कि अब बांस को, बाम्बू को पेड़ की श्रेणी में नहीं, उसको ग्रास की श्रेणी में रखा जाएगा ताकि किसान अपने खेत के मेढ़ पर बाम्बू की खेती कर सकता है, बाम्बू बेच सकता है, बाम्बू से अलग-अलग चीजें बना करके बाजार में बेच सकता है, गांव के अंदर एक नया रोजगार पैदा हो सकता है।

आप हैरान होंगे इतने जंगल, इतने जनजाति का मेरा समुदाय, इतने बाम्बू, लेकिन मेरे देश में 12-15 हजार करोड़ रुपये के बाम्बू हम विदेशों से लाते हैं। अगरबत्ती बनानी है बाम्बू विदेश से लाओ, दियासलाई बनानी है बाम्बू विदेश से लाओ, पंतग बनाना है, बाम्बू विदेश से लाओ। घर बनाना है, बाम्बू काटने की इजाजत नहीं। हजारों करोड़ रुपया विदेश चला जाता है।

अब मैं मेरे जनजातीय भाइयों को गांव के मेरे किसानों से आग्रह करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का बाम्बू अपने खेत की मेढ़ पर, बाकी जो खेती करते हैं वो करते रहें हम, खेत के किनारे पर अगर हम बाम्बू लगा दें, दो साल में, तीन साल में वो कमाई करना शुरू कर देगा। मेरे किसान की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जो जमीन बेकार पड़ी थी किनारे पर वहां अतिरिक्त आय होगी कि नहीं होगी?

मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ क्या हम कृषि के क्षेत्र में हमारे गांव के किसानों को आत्मनिर्भर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारे हिमाचल के गर्वनर साहब हैं, देवव्रत जी। वे गर्वनर हैं लेकिन पूरा समय जीरो बजट वाली खेती लोगों को सिखाते रहते हैं। एक गाय हो एक गाय, और दो एकड़ भूमि हो, तो कैसे जीरो बजट से खेती हो सकती है, वो सिखाते रहते हैं और कई लोगों ने उस प्रकार से रास्ता बनाया है। क्या मेरे पंचायत के प्रतिनिधि इन चीजों को सीख करके अपने गांव के किसानों को तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?

अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं शहद का। मधुमक्खी पालन का। अगर छोटा सा भी किसान हो, अगर 50 पेटी अपने खेत में रख लें तो साल भर में डेढ़-दो लाख रुपयों का शहद बेच सकता है और अगर बिका नहीं, गांव में खाया भी, तो भी शरीर को लाभ हो जाएगा। आप मुझे बताइए खेती की इन्कम में बढ़ोत्तरी हो सकती है कि नहीं? क्या ये काम बजट से करने की जरूरत है, जी नहीं। ये काम अपने-आप हो सकते हैं। और इसलिए हम तय करें।

अब मनरेगा का पैसा आता है, लोगों को सरकार, भारत सरकार पैसे भेजती है। मजदूरी के लिए पैसे देती है। क्या हम अभी से तय कर सकते हैं कि भाई अप्रैल, मई, जून- तीन महीना जो मनरेगा का काम होगा, जो हम मजदूरी देंगे, हम पहले तय करेंगे कि गांव में पानी बचाने के लिए क्या-क्या काम हो सकते हैं। अगर तालाब गहरा करना है, छोटे-छोटे check dam बनाने हैं, पानी रोकने का प्रबंध करना है। बारिश की एक-एक बूंद, ये पानी बचाने के लिए ही तीन महीने मनरेगा के पैसों का काम, उसी में लगाएं। जो भी मजदूरी का काम करेंगे, उसी काम के लिए करेंगे।

आप मुझे बताइए अगर गांव का पानी गांव में रहता है, बारिश का एक-एक बूंद का पानी बच जाता है तो जमीन में पानी जो गहरे जा रहे हैं वो पानी ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे? पानी निकालने का खर्चा कम होगा कि नहीं होगा? अगर बारिश कम अधिक हो गई तो उसी पानी से खेती को जीवनदान मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? गांव को कोई भूखा मरने की नौबत आएगी की क्या?

ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है। मैं गांव के प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, आप तय करें- चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे पानी बचाने का मामला हो, चाहे कृषि के अंदर बदलाव लाने का मामला हो, ये ऐसे काम हैं जिसमें नए बजट के बिना भी गांव के लोग आज जहाँ हैं वहां से आगे जा सकते हैं।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा - एक योजना हमने लागू की थी जनधन योजना, बैंक का खाता। दूसरी योजना ली थी 90 पैसे में बीमा योजना। मैं नहीं मानता हूं गरीब का, गरीब से गरीब 90 पैसे खर्च नहीं कर सकता है। अगर उसको बीड़ी पीने की आदत होगी तो शायद वो दिन में दो रुपये की तो बीड़ी पी लेता होगा। 90 पैसे वो निकाल सकता है।

आपने देखा होगा यहां मंच पर मुझे एक जनजाति समुदाय की मां को दो लाख रुपया देने का सौभाग्य मिला। ये दो लाख रुपये क्या थे? उसने जो 90 पैसे वाला बीमा लिया था और उसके परिवार में आपत्ति आ गई, परिवार के मुखिया का स्वर्गवास हो गया। उस 90 पैसे की बदौलत आज उसको दो लाख रुपये का बीमा मिल गया। एक गरीब मां के हाथ में दो लाख रुपया आ जाए, मुझे बताइए जिंदगी की इस मुसीबत के समय उसकी जिंदगी को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी?

क्या मेरा जनप्रतिनिधि, क्या मेरा पंचायत का प्रधान मेरे गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका प्रधानमंत्री जनधन खाता नहीं होगा और जिसका कम से कम 90 पैसे वाला बीमा नहीं होगा, और अगर उस परिवार में मुसीबत आई तो दो लाख रुपया उस परिवार को मदद मिल जाएगी। गांव पर वो परिवार कभी बोझ नहीं बनेगा, क्या ये काम नहीं कर सकते हैं?

भाइयो, बहनों, तीन चीजों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वो- एक जनधन, दूसरा वनधन और तीसरा गोबरधन, गोबरधन। ये तीन चीजों से हम गांव की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जनधन योजना से अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में हमारे परिवार को, हर नागरिक को ला सकते हैं।

वनधन- हमारे यहां जो वन संपदाएं हैं, जो प्राकृति संपदाएं हैं; उसका मूल्य समझ करके- अरे आज तो, अगर गांव के अंदर नीम का पेड़ है और नीम की फली नीचे गिरती है- अगर पांच-पच्चीस महिलाएं उस नीम की फली इकट्ठी कर लें, उसका तेल निकलता है और यूरिया का नीम कोटिंग होता है, गांव की महिला को भी कमाई हो जाती है। वो नीम का पेड़, नीम की फली कभी मिट्टी में मिल जाती थी, आज- आज वो वनधन बन सकती है। क्या हम ये बदलाव नहीं ला सकते हैं?

मैं जंगलों में रहने वाले मेरे सभी जनजातीय बंधुओं से कहना चाहूंगा, मैं सभी सरकारों से भी कहना चाहूंगा। और आज यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी योजना को लॉन्च किया है। जिसमें वनधन का भी महात्म्य है।

तीसरी बात मैंने कही- गोबरधन। गांव में पशु होते हैं, जो गोबर है उसका वैज्ञानिक तरीके से उपयोग नहीं होता है। अगर गांव का गोबर, गांव को कूड़ा-कचरा, इसको एक संपत्ति मानें, उसमें से गैस पैदा हो सकती है, उसमें से बिजली निकल सकती है, उसमें से उत्तम प्रकार का खाद बन सकता है। यूरिया की जरूरत के बिना उत्तम खाद से गांव की खेती चल सकती है। गांव में बीमारी नहीं आ सकती है। ये काम भी पैसों के बिना हो सकता है। सरकार की योजनाओं का लाभ ले करके हो सकता है।

और इसलिए भाइयो, बहनों, आज जब मैं देशभर के पंचायतों के चुने हुए लोगों के साथ हिन्दुस्तान के सभी गांवों में, दो लाख चालीस हजार गांवों को, आज मां नर्मदा की धरती से, मंडला की धरती से, माता दुर्गावती के आशीर्वाद के साथ आज जब मैं संबोधन कर रहा हूं तब मैं आपसे आग्रह करता हूं- आइए हम संकल्प करें- 2022, जब आजादी के 75 साल होंगे, और इसी वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का प्रारंभ होगा, ये ऐसा हमारे लिए अवसर है कि हम गांधी के सपनों का गांव बनाएं। हम मिल करके भारत को बदलने के लिए गांव को बदलें। हम सब मिल करके गांव के अंदर पैसों का सही इस्तेमाल करें।

आज अभी एक कार्यक्रम मैंने लॉन्च किया जिसके तहत टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार से कितना पैसा आता है, किस काम के लिए आता है, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, जहां होना चाहिए वहां हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा ब्यौरा अब आप अपने मोबाइल फोन पर देख पाएंगे। आपको पता चलेगा कि कुएं के लिए पैसा आया था, लेकिन कुंआ तो कहीं नजर नहीं आया तो आप गांव में पूछोगे कि भाई ये तो जो सरकार ने व्यवस्था की, इस पर तो दिखता नहीं है कुंआ। तो गांव वाला भी सोचगा हां भाई रह गया है चलो महीने में करवा देता हूं। मुझे बताइए हिसाब-किताब बनेगा कि नहीं बनेगा? गांव में ईमानदारी से काम करने की आदत आएगी कि नहीं आएगी? बाबुओं को काम का जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?

और इसलिए मेरे प्यारे भाइयो, बहनों सही समय पर सही काम- आप देखिए पांच साल का हमारा कार्यक्रम स्वर्णिम कार्यकाल बना सकता है। गांव याद करेगा कि भाई फलाने वर्ष से फलाने वर्ष तो जो बॉडी चुन करके आई थी उसने गांव की शक्ल-सूरत बदल दी। इस संकल्प को ले करके आगे चलना और इसी के लिए आज मुझे यहां एक एलपीजी के प्लांट का लोकार्पण करने का अवसर मिला और ये एलपीजी प्लांट का जो मैंने लोकार्पण किया, आपने देखा होगा कि हम गैस तो पहुंचा रहे हैं लोगों को, लेकिन अब वो गैस भरने के जो सिलिंडर हैं, उसके कारखाने लगाने पड़ रहे हैं। यहीं पर 120 करोड़ रुपये की लागत से ये कारखाना लगेगा। गैस सिलिंडर भरने का काम होगा और ये व्यवस्था कहते हैं अगल-बगल में पन्ना हो, सतना हो, रीवा हो, सिंगरौली हो, शहडोल हो, उमरिया हो, डिंडोरी हो, अनुपुर हो, मंडला हो, सीवन हो, बालाघाट हो, जबलपुर हो, कटनी हो, दमोह हो; इन सारे डिस्ट्रिक्ट में ये गैस सिलिंडर पहुंचाने का काम सरल हो जाएगा। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और आपके यहां एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी। ये काम भी आज मुझे आपके बीच में करने का अवसर मिला है।

भाइयो, बहनों, कई विषय हैं जिसकी मैं चर्चा कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं हम ग्राम केन्द्री जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान इस मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जाना है।

अब आप लोगों ने देखा- मैं देख रहा था कि अभी जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पर लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था

पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था। तालियां बंद नहीं हो रही थीं। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है।

और मैं कहूंगा, हम परिवार में बेटियों को सम्मान देना सीखें, हम परिवार में बेटियों का महात्म्य बढ़ाएं और परिवार में जरा बेटों को जिम्मेदारी सिखाना भी शुरू करें। अगर बेटों को जिम्मेदारी सिखाना शुरू करेंगे तो बेटियों को सुरक्षित करना कभी कठिन नहीं होगा और इसलिए जो बड़मानी करेगा, जो भ्रष्ट आचरण करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो तो फांसी पर लटक जाएगा। लेकिन हमने हमारे परिवारों में भी हमारी बेटियों के मान-सम्मान का जिम्मा उठाना पड़ेगा। एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना होगा। और हम सब मिल करके देश को ऐसी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे।

भाइयो, बहनों, सरकार ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम सोचा हुआ है। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी की लड़ाई कुछ ही लोगों के आसपास, कुछ ही परिवारों के आसपास सिमट गई। सच्चे बलिदानियों की कथा इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज होने से पता नहीं क्या मुसीबत आई, मैं नहीं जानता।

अगर 1857 से देखें, उसके पहले भी सैंकड़ों सालों की गुलामी के कालखंड में कोई एक वर्ष ऐसा नहीं गया है कि हिन्दुस्तान के किसी न किसी इलाके में आत्मसम्मान के लिए, संस्कृति के लिए, आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान न दिया हो। सैंकड़ों सालों तक लगातार दिया है। लेकिन मानों 1857 के बाद भी देखें, बहुत कम लोगों को पता है और हमें भुला दिया गया है कि मेरे जनजाति के भाइयों-बहनों ने भारत की आजादी के लिए कितने बलिदान दिए हैं। भारत के सम्मान के लिए कितनी बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। दुर्गावती, अवन्तीबाई को तो याद करते हैं, बिरसा मुंडा को याद करते हैं, कितने लोगों ने दिए हैं।

मेरा सपना है हिन्दुस्तान के हर राज्य में, जहां-जहां जनजातीय समुदाय के हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उनका हर राज्य में एक आधुनिक म्यूजियम बनाया जाएगा। स्कूल के बच्चों को वहां ले जाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि ये हमारे जंगलों में रहने वाले हमारे जनजातीय बंधुओं ने हमारे देश की संस्कृति और इतिहास के लिए कितने बलिदान दिए थे और आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश में भी ये काम होने वाला है।

और इसलिए मेरे भाइयो, बहनों, आज हम मंडला की धरती से मां दुर्गावती का स्मरण करते हुए आदि मेला कर रहे हैं, तब, पंचायतराज के भी इस महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा पंचायतराज का सशक्तिकरण हो, हमारी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, हमारे जनप्रतिनिधि मां भारती के कल्याण के लिए, अपने गांव के कल्याण के लिए अपने-आपको खपा दें। इसी एक भावना के साथ मैं आप सबको हृदयपूर्वक बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान तोमर जी, रूपाला जी और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। क्योंकि उन्होंने देशभर में ग्राम स्वराज अभियान चलाया है।

आने वाली 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत का लोक-जागरण होने वाला है। 2 मई को किसानों के लिए कार्यशालाएं होने वाली हैं। गांव के जीवन से जुड़ी हुई बातें जुड़ने वाली हैं। आप सब बड़े उत्साह और उमंग के साथ उसके साथ जुड़ें।

इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/ शाहबाज़ हसीबी/सतीश शर्मा/ निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1533003) आगंतुक पटल : 89

प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 05 JUN 2018 5:24PM by PIB Delhi

मेरे प्यारे भाईयो और बहनों, नमस्कार,

मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अलग-अलग योजनाओं से सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आया है। उन अनुभवों को सीधे उन्हीं लोगों से बातचीत करते हुए मैं जानता हूँ और इसलिए मैं अक्सर ऐसे लाभार्थियों से सीधे मुलाकात करने का प्रयास करता हूँ। सही हो गलत हो, अच्छा हो खराब हो, दिक्कतें आई हों, सहूलियतें मिली हों। इन सबके बारे में सीधे आप जैसे लोगों से जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सरकार में अफसरों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार होती हैं। उसका अपना एक महत्व है ही लेकिन प्रत्यक्ष जीने से लाभ मिला और जिन लोगों को लाभ मिला। उनसे जब संवाद करके नई चीज सुना जैसे उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन। मैं उस उज्ज्वला के लिए काफी बातें करता था। लेकिन जब उज्ज्वला के लाभार्थियों से मिला तो उन्होंने बड़ी मजेदार बताई मेरे को बात, उन्होंने कहा हमारा पानी बच गया, मैंने कहा पानी कैसे बच गया? तो पहले बोले लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाते थे तो सारे बर्तन काले हो जाते थे और दिन में चार चार बार बर्तन साफ करने के लिए बहुत पानी लगता था। अब गैस का चूल्हा आ गया तो हमें वो करना नहीं पड़ रहा है। अब ये बात मैं नहीं मानता हूँ कि मैं उनसे बात करता तो मुझे समझ आती, ऐसी बहुत सी बातें हैं। जब मैं खुद बात करता हूँ और उसी सिलसिले में आज मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं या वो लोग जिनके सामने घर तैयार हो रहा है। घर बनाने में जुड़े हैं। जिनको कुछ ही समय में घर मिलना निश्चित है। ऐसे सब लोगों से रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का एक अवसर मिला है।

आप जानते हैं हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा हमेशा रहती है कि मेरा खुद का अपना घर हो गरीब से गरीब को भी लगता है कि भाई मेरा अपना घर हो। भले छोटा ही क्यों न हो और अपना घर होने की जो सुखद अनुभूति होती है। वो...जिसे घर मिला है वही जानता है और कोई नहीं जानता। और मैं जो आपको टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहा हूँ। आपके चेहरे पर जो खुशी है, एक संतोष का भाव है। जीवन जीने का एक नया उमंग पैदा हुआ है। ये ये मैं देख रहा हूँ। और जब मैं आपका उत्साह और उमंग मैं अपनी आंखों से देखता हूँ तो मेरा उत्साह और उमंग भी दस गुना बढ़ जाता है। फिर मेरा भी मन करता है और ज्यादा काम करूँ। आपके लिए और मेहनत करूँ। क्योंकि आपके चेहरे की खुशी मुझे देखने को मिलती है और वही मेरी खुशी का कारण है।

किसी भी आवास योजना का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को सिर छुपाने की मात्र जगह देनी है। आवास का मतलब घर से है सिर्फ चारदीवारी और छत से नहीं है। घर यानी वो जगह.. जहां जीवन जीने लायक हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। जिसमें परिवार की खुशियां हों। जिसमें परिवार के हर व्यक्ति के सपनें जुड़े हुए हों।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मूल में भी यही भाव है। अपना घर हर किसी का सपना होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भी ये इच्छा रहती है कि उसके पास अपना पक्का घर हो लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी गरीब की इच्छा अधूरी ही है। इस सरकार ने संकल्प लिया और तय किया कि 2022, जब हमारी आजादी के 75 साल हो जाएंगे तो कुछ हम, ऐसे अवसर होते हैं कि जब सबको दौड़ने का मन कर जाता है। चलो भई आजादी के 75 साल हुए हैं चलो कुछ काम करें, ज्यादा करें, अच्छा करें, सब लोगों की भलाई करें।

हमने भी कोशिश की है कि 2022 आजादी के 75 साल हमें ये पांच साल, चार साल जो भी समय मिला है। दौड़ने की हिम्मत आ जाए, काम करने की हिम्मत आ जाए। और उसने एक सपना लिया है 2022 आजादी के 75 साल हिन्दुस्तान के हर परिवार के पास गरीब से गरीब हो, गांव हो शहर हो, झुग्गी-झोंपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो। उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और सिर्फ घर ही नहीं, उसमें बिजली हो, नल हो.. नल में जल हो, गैस का चूल्हा हो, सौभाग्य की बिजली हो, शौचालय हो, यानी एक प्रकार से उसको लगना चाहिए कि हां अब जिंदगी जीने के योग्य बन गई हैं। अब कुछ और करके आगे बढ़ने के रास्ते बने, गरीब से गरीब आदमी को भी सिर्फ विश्राम के लिए ही जगह न मिले बल्कि मान-सम्मान और परिवार की गरिमा बढ़ाने का भी अवसर मिले। Housing for all सबके लिए घर ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। मतलब आपका सपना, मेरा सपना, आपका सपना देश की सरकार का सपना है।

करोड़ों लोगों के विशाल देश में ये संकल्प पूरा करना मामूली काम नहीं है। चुनौती बहुत बड़ी है, कठिन है। और आजादी के इतने सालों का अनुभव कहता है कि ये सब संभव ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये गरीब की जिंदगी है। बिना घर रहने वालों की जिंदगी है। जिसने मुझे ये निर्णय करने की हिम्मत दी है। आपके प्रति प्यार ने, आपके प्रति मेरे दिल में जो लगाव है उसके कारण इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब निर्णय पूरा करने में सरकारी मशीनरी, बाकि लोग भी मदद में है। काम हो रहा है। लेकिन ये तब होता है, सिर्फ इच्छा शक्ति से थोड़े ही हो जाता है। उसके लिए योजना चाहिए, इसके लिए गति चाहिए। जनता का विश्वास और समर्थन चाहिए। जनता के लिए समर्पण का भाव चाहिए। इस चुनौती से निपटने के लिए पहले की सरकारों के जो काम-काज है। कैसे काम होता था, कैसे शुरू करते थे। कहां जाकर पहुंचते थे। सब आप लोग जानते हैं।

मैं समझता हूं कि आज उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमने कहीं मंदिरों, समुदायों के नाम पर, कहीं झुग्गी-झोंपड़ी के नाम पर मकान बनाना, काम शुरू किया, लेकिन बढ़ती आबादी के नाम पर ये प्रयास नाकाफी ही साबित हुआ। बाद में ये योजना व्यक्तियों के नाम पर बनने लगी, परिवारों के नाम पर बनने लगी। स्वाभाविक तौर पर इनका उद्देश्य सामान्य मानवी को घर देने के बजाय राजनीतिक हितों को साधने का अधिक हो गया था। बिचौलियों की बहुत बड़ी फौज बन गई थी और ठेकेदार जब माला माल चलता था। हमने एक अलग approach के साथ इस चुनौती पर काम किया। टुकड़ों में सोचने के बजाय मिशन मोड में काम करने का संकल्प ले लिया। हमने तय किया है कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में तीन करोड़ और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ घरों का निर्माण करेंगे। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो स्वाभाविक है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट भी बड़ा चाहिए। एक समय था जब बजट आबंटन के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित किया जाता था। लेकिन अब हम पहले लक्ष्य तय करते हैं। देश को किसको पहले जरूरत है, कितनी जरूरत है उसके आधार पर लक्ष्य तय करते हैं। फिर उसके अनुसार बजट निर्धारित करते हैं। इसी का परिणाम है कि शहरी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो हमारे पहले जो सरकार थी वो गरीबों के नाम पर ही खेल खेलती रहती थी।

यूपीए सरकार के दस वर्षों में जितने घरों को, निर्माण को मंजूरी भी नहीं दी पिछले चार वर्षों में हमने उसका लगभग चार गुना अधिक सैंक्शन किया है। यूपीए सरकार के दस वर्ष में कुल साढ़े तेरह लाख घर सैंक्शन किए गए थे जबकि हमारी सरकार के तहत पिछले चार साल में 47 लाख यानी करीब-करीब 47 लाख, एक प्रकार से 50 लाख के पार पहुंचने के अधिक घर हमने सैंक्शन कर दिए हैं। इनमें से 7 लाख घर नई टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं।

अब housing में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ देने के लिए Global Housing Technology Challenge ये शुरू कर रहे हैं। ताकि Low Cost Housing की नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके। इसी तरह यदि गांव की बात करें तो पिछली सरकार के अंतिम चार साल में गांव के अंदर पूरे हिन्दुस्तान में करीब-करीब साढ़े 25 लाख घरों का निर्माण किया गया था। वहीं हमारी सरकार ने पिछले चार वर्ष में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया है। यानी सवा तीन सौ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि। पहले मकान बनाने के लिए 18 महीने का समय तय था। लेकिन हमने इसको घटाकर के इसको महत्व समझते हुए, गति तेज करते हुए 18 महीने का काम 12 महीने में पूरा करने का संकल्प करके हम आगे बढ़ रहे हैं।

अब स्थिति ये है कि एक वर्ष से भी कम समय में घर बनकर तैयार हो रहा है, आज घरों के निर्माण में तेजी आ रही है, और ये देखिए कैसे आ रही है। सिर्फ ईंट और पत्थर तेज गति से हम डाल दें तो घर बन जाता है ऐसा नहीं है। इसके लिए सभी स्तरों पर योजनाबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाए जाते हैं। स्केल ही नहीं, साइज को लेकर भी परिवर्तन किया गया है। गांव में पहले घर बनाने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर था जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब हम लोगों ने आकर के इसे 20 वर्ग मीटर की जगह 25 वर्ग मीटर कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि इस 5 वर्ग मीटर का ही फर्क लेकर जगह बढ़ जाने से क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक अलग साफ सुथरा रसोई घर अब इसमें जुड़ गया।

गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले 70-75 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी। जिसे अब हमने बढ़ाकर के सवा लाख रुपये कर दिया है। आज लाभार्थियों को मनरेगा से 90-95 दिनों का मेहनताना मजदूरी के लिए भी उसके खाते में जमा होता है।

इसके अलावा आज शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये अलग से दिए जा रहे हैं। पहले देखने को मिलता था कि बिचौलियों के नेताओं के घर तो बन जाते थे। लेकिन गरीब का घर नहीं बनता था। गरीबों के पैसे में कोई सेंध न मारे, उसे कोई और न ले जाए इसके लिए हमने पक्की व्यवस्था बनाई है।

आज डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बिचौलिये खत्म हुए। और लाभार्थियों को सब्सिडी और सहायता राशि सीधे उनके खाते में दी जा रही है। पहले जनधन अकाउंट खोला अब रुपया भेजना शुरू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम की प्रगति की monitoring के लिए ये जो घर बन रहे हैं, जो आवास बन रहे हैं। उनकी Geo ट्रेकिंग की व्यवस्था की है। ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इन कामों को DISHA पोर्टल से भी जोड़ा गया है। जहां ये देखा जा सकता है कि आप monitor कर सकते हैं। मैं मेरे ऑफिस से monitor कर सकता हूं कि कितना काम हुआ है कहां-कहां हुआ है। उसका पूरा detail मैं मेरे दफ्तर में बैठकर के भी देख सकता हूं।

यूपीए के कार्यकाल में लाभार्थियों का चयन जो पुरानी राजनेताओं ने तैयार की हुई बीपीएल सूची से किया जाता था लेकिन आज हम लोगों ने Socio Economic Caste Census के माध्यम से करना शुरू किया उसके कारण पहले जो छूट जाते थे। अब उनको भी हमने जोड़ दिया है। और इसके कारण अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके उनको लाभ मिला है। हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

घर सिर्फ जरूरतों से नहीं, घर सम्मान से भी जुड़ा होता है, स्वाभिमान से जुड़ा होता है। और एक बार अपना घर बन जाता है। तो घर के हर सदस्य की सोच भी बदलती है। आगे बढ़ने का नया हौसला पैदा होता है।

हमारा प्रयास है कि हर परिवार की इस जरूरत को पूरा करना और उसके सम्मान को बढ़ाना और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फोकस विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर ही हमने केंद्रित किया है। आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरटी और हमारे दिव्यांग भाई-बहन उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं।

इस तरह योजनाबद्ध तरीके से व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज तेजी से घरों का निर्माण हो रहा है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। सामान्य जन की समस्याओं को, उनकी पीड़ा को हम भली-भांति जानते हैं, समझते हैं और यही कारण है कि हम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर के काम कर रहे हैं। सरकारों में ऐसा चलता आया है। कि हर योजना अलग-अलग काम करती है। पहला मंत्रालयों के बीच, दो विभागों के बीच, दो योजनाओं के बीच समन्वय ही नहीं होता।

प्रधानमंत्री आवास योजना में विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ लाया गया है, जोड़ा गया है। निर्माण और रोजगार के लिए इसे मनरेगा से जोड़ा गया। घर में शौचालय, बिजली, पानी और एलपीजी गैस की सुविधा हो इसका ध्यान अलग से रखा गया। घर में शौचालय हो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया। घर में बिजली की सुविधा हो इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना को इसके साथ लिंक कर दिया गया। पानी की सुविधा के लिए इसे ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से जोड़ा गया। एलपीजी की व्यवस्था हो

इसके लिए उज्ज्वला योजना को इससे जोड़ा गया। ये आवास योजना सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। बल्कि ये सशक्तिकरण का भी माध्यम है। शहरों में जिनको मकान का लाभ मिला है। उनमें 70 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर है।

आज जब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घर बन रहे हैं तो इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर ईंट, रेत, सीमेंट से लेकर हर प्रकार की निर्माण सामग्री का व्यापार बढ़ रहा है। स्थानीय श्रमिकों, कारीगरों को भी काम मिल रहा है। इसके साथ-साथ गांव में गुणवत्तापूर्वक कार्य के लिए सरकार ने एक लाख राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है, masons का और आपको ये जान करके भी खुशी होगी कि और कई राज्यों में राज मिस्त्री की तरह रानी मिस्त्रियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है।

शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत सम्मिलित करने के लिए सरकार ने चार मॉडल पर काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को घर बनाने या उसका विस्तार करने के लिए प्रतिघर डेढ़ लाख रुपये की सहायता की जा रही है।

लिंग सब्सिडी स्कीम के तहत घर बनाने हेतु किए गए लोन पर ब्याज में 3 से 6 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। एरिया में redevelopment के लिए सरकार प्रति घर 1 लाख रुपये की सहायता दे रही है। या पब्लिक सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में किफायती आवास, affordable housing के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्रति घर डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। पहले देखने को मिलता था कि बिल्डर्स पैसा तो ले लेते थे। लेकिन सालों तक एक ईंट भी नहीं लगती थी। गरीब और मध्यम वर्ग का फायदा हो। घर खरीददारों के हितों की रक्षा की जा सके। मध्यम वर्गीय परिवार जिंदगी की सारी कमाई मकान बनवाने के लिए लगाता है उसको कोई लूट न ले जाए। इसके लिए हमने RERA- Real Estate Regulation Act लागू किया। इस कानून से पारदर्शिता आने के साथ-साथ खरीददार को उनका हक मिल रहा है। और बिल्डर्स भी खरीददार से किसी भी प्रकार का धोखा करने से डरते हैं।

आज देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी आशाओं और आकांक्षाओं को इस योजना ने पंख लगाए हैं। घर होने से समृद्धि और सुरक्षा तो बढ़ती ही है। और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अपना घर होना सबकी पहली प्राथमिकता होती है, पहले भी होती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि पहले ये सबसे आखिर में पूरी होती थी। और कभी-कभी अधूरी ही रह जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है।

हम सब हमेशा सुनते आए हैं। एक जिंदगी बीत जाती है अपना घर बनाने में। सुनी है ये कहावत, पूरी जिंदगी बीत जाती है अपना घर बनाने में। पर अब ये सरकार दूसरी है। अब कहावत भी बदल रही है, देश बदल रहा है कहावत भी बदल रही है। और कहावत को बदलने का समय आ गया है। अब समय आ गया है जब हमारे अंदर से आवाज उठेगी कि अब जिंदगी बीतती है अपने ही आशियाने में।

मैं मानता हूँ कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था है तो अभी भी कुछ लोग होंगे जिनकी पुरानी आदतें बदली नहीं होंगी। और इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि इस योजना के तहत किसी भी तरह का लाभ पहुंचाने के लिए अगर आपसे कोई पैसा या कोई अनावश्यक मांग कर रहा हो। तो आप बेहिचक इसकी शिकायत करें। इसके लिए आप कलेक्टर या मिनिस्टर के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

मैंने पहले भी कहा है कि भारत के सपने और आकांक्षाएं इतने भर से ही पूरे नहीं होती। हमने एक मजबूत जमीन तैयार की है। और हमारे सामने एक असीम आसमान है। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन, ये इस न्यू इंडिया की सम्पूर्णता की तस्वीर होगी।

आधुनिक सुविधाओं से जुड़े गांवों और समाज की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए कितनी बड़ी तादाद में भाईयो बहनों से आज मुझे मौका मिला है बात करने का.... एक छोटा सा विडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ।

अतुल तिवारी/ हिमांशु सिंह

(रिलीज़ आईडी: 1536152) आगंतुक पटल : 195

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Marathi , Assamese , Tamil , Kannada

प्रधानमंत्री कार्यालय

डिजिटल इंडिया लाभार्थियों के साथ संवाद के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 15 JUN 2018 5:19PM by PIB Delhi

पिछले कुछ दिनों से मुझे सरकार की विभिन्न योजनाओं के देश भर के जो लाभार्थी हैं। उन सबसे रूबरू होने का, बातचीत करने का उनको सुनने का अवसर मिला और मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव है। और मैं हमेशा इस हिम्मत का आग्रही हूँ। कि फाइलों से परे लाइफ भी होती है। और लाइफ में जो बदलाव आया है। जब उसको सीधा लोगों से सुना। उनके अनुभवों को जाना तो मन को एक बहुत ही संतोष मिलता है। और काम करने की एक नई ऊर्जा भी मुझे आप लोगों से मिली है। आज डिजिटल इंडिया की कुछ योजना के लाभार्थियों से बातचीत करने का अवसर मिला है।

मुझे बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में देश भर के गरीब 3 लाख Common Service Centres इनके साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला है। इन CSC Common Service Centre को संचालित करने वाले VLEs और जो नागरिक इनसे अलग-अलग तरह की सेवाएं ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। वे सब आज यहां मौजूद हैं। इसके अलावा देश भर के NIC centre के माध्यम से Digital India के लाभार्थी वहां भी इकट्ठा हुए हैं। 1600 से अधिक संस्थाएं जो NKN National Knowledge Network उनसे जुड़े हैं। उनके विद्यार्थी, Researchers, Scientist, Professors ये सब हमारे साथ हैं। देश भर में सरकार की योजना से जो BPO स्थापित हुए हैं। उनके युवा अपने-अपने BPO centre से भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ है। इतना ही नहीं Mobile, Manufacturing Units में काम करने वाले युवा भी हमें अपनी-अपनी Units भी दिखाएंगे। और वो कुछ बात हमसे करेंगे।

देश भर में लाखों की संख्या में Mygov volunteers भी जुड़े हैं। मैं मानता हूँ ये अनोखा संवाद है जहां कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग एक ही विषय पर आज हम सब मिलकर के बातें करने वाले हैं। हर किसी का अनुभव सुनने का, उनसे बातचीत करने का एक ही अद्भुत अवसर है और जब Digital India launch हुआ था तो एक संकल्प था कि देश के सामान्य व्यक्ति को, गरीब को, किसानों को, युवाओं को, गांवों को डिजिटल की दुनिया से जोड़ रहा है। उन्हें Empower कर रहा है। इसी एक संकल्प को लेकर पिछले चार साल में Digital Empowerment के हर एक पहलू पर काम किया है चाहे गांवों को, Fibre Optics से जोड़ना हो। करोड़ों लोगों को डिजिटली साक्षर करना हो, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से हर एक के हाथ में पहुंचाना हो, Electronic Manufacturing को देश में विकसित करना हो Strat up or Innovation को बढ़ावा देना हो, दूर-दराज के क्षेत्रों में BPO's खोलने को अभियान चलाना हो। ऐसे अनेक प्रकल्प आज पेंशन प्राप्त करने वाले हमारे बुजुर्गों को कोसो दूर खुद जाकर अपने जीवन का प्रमाण नहीं देना पड़ता बल्कि वो अपने गांव में ही Common Service Centres CSC centre से पहुंच करके बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। देश का किसान मौसम का हाल जानना हो, फसल के संबंध में जानकारी लेनी हो, Soil आदि के बारे में जानकारी लेनी हो। वो बड़े आराम से आजकल प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ एक Digital Market ENAM के माध्यम से अपने उत्पाद भी देश भर के बाजारों में वो बेच सकता है। अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या CSC के सेंटर पर जाकर।

आज गांव में पढ़ने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने स्कूल-कॉलेज में उपलब्ध किताबों तक सीमित नहीं है। वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके digital library के जरिये लाखों किताबों का access कर रहा है। वो अब scholarship की धनराशि के लिए स्कूल-कॉलेज के प्लानिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं है। उसकी scholarship अब सीधा उसके बैंक खाते में आ जाती है। ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचार क्रांति के द्वारा। आज से कुछ वर्ष पहले

तक महानगरों से दूर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में रहने वालों के लिए इस बात की कल्पना भी मुश्किल थी कि रेलवे टिकट बिना स्टेशन पर गए हुए, बिना लाइन में लगे हुए रेलवे टिकट बुक हो सकती है। या रसोई गैस बिना लाइन में घंटों बिताए सीधा घर तक पहुंच सकती है। टैक्स, बिजली, पानी का बिल बिना किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाए ही जमा हो सकता है। लेकिन आज ये सब संभव है आपके जीवन से जुड़े हुए तमाम जरूरी काम अब बस अंगुली भर की दूरी पर है। और ऐसा नहीं है कि कुछ चंद लोगों को ही ये उपलब्ध है, हर एक को उपलब्ध है। देश के हर नागरिक को अधिक से अधिक सुविधाएं अपने घर के पास ही मिल सके। इसके लिए देश भर के Common Service Centres CSC network को मजबूत किया जा रहा है।

अब तक देश में करीब 3 लाख Common Service Centres खोले जा चुके हैं। आज Digital Service Deliver Centres का ये विशाल नेटवर्क भारत के 1 लाख 83 हजार ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है। आज लाखों की संख्या में युवा Village Level Entrepreneurs (VLE) के रूप में काम कर रहा है। और खुशी की बात है कि इनमें 52 हजार महिलाएं उद्यमी काम कर रही हैं।

इन केंद्रों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। समग्र रूप से देखें तो ये केंद्र न सिर्फ Empowerment का माध्यम बने हैं बल्कि इससे Education, Entrepreneurship or Employment को भी बढ़ावा मिला है।

मेरे हिन्दुस्तान में जो बदलाव आ रहा है, जो बदलाव आप लोग ला रहे हैं और अपनी अंगुली की ताकत से ला रहे हैं, ये प्रगति, ये विश्वास, ये विकास, Reform Perform Transform इसको साकार करने वाला है। फिर एक बार आप सब को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

नमस्कार।

एकेटी/वीजे

(रिलीज़ आईडी: 1535648) आगंतुक पटल : 176

प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रधानमंत्री के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 27 JUN 2018 8:17PM by PIB Delhi

ये वो लोग हैं जिन्होंने समय रहते समझदारी भरे कदम उठाए और जीवन की हर चुनौती के लिए खुद को तैयार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो बातें बताएंगे वो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करेंगी। हम सब जानते हैं कि जीवन में एक बात बहुत निश्चित है और वो है जीवन की अनिश्चितता। हम में से कोई ये नहीं जानता है कि आने वाला कल, आने वाला पल हमारे जीवन में क्या ले करके आने वाला है।

जन सुरक्षा योजनाएं जीवन की अनिश्चितताओं और परिस्थितियों से जूझने की और जूझ करके जीतने की हिम्मत देती हैं। और ये हिम्मत अब देश के करोड़ों लोगों तक पहुंची है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो या प्रधानमंत्री वय-वंदना योजना हो।

जन सुरक्षा योजनाएं आमजन को और खासतौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बना रही हैं। जिससे संकट के समय वो मजबूती के साथ खड़े रह सकें, जीवन से हार न जाएं। जब हमारी सरकार बनी, हम सरकार में आए तो आर्थिक सहायता तो दूर की बात, गरीब के पास अपना बैंक खाता भी नहीं था।

हमने तीन बातों पर जोर दिया – दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिला; इन सबको सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों तक बैंक की सुविधा पहुंचाना। लघु उद्योग और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और वित्तीय रूप से असुरक्षित लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी Banking the unbanked, funding the unfunded and financially securing the unsecured.

और आप सब लोगों को बहुत खुशी होगी कि विश्व बैंक की Fintax Report में कहा गया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना एक सफल financial inclusion program रहा, जिसमें तीन साल में, 2014 से 2017 की अवधि में 28 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए। यह संख्या इस अवधि के दौरान पूरे विश्व में खोले गए सभी नए बैंक अकाउंट का 55 प्रतिशत है – आधे से ज्यादा। पहले हमारे यहां कहावत होती थी – एक बाजू राम, एक बाजू गांव, यानी एक तरफ हिन्दुस्तान और एक तरफ पूरी दुनिया।

इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में बैंक खाते रखने वाले लोगों की संख्या 2014 में, यानी हमारी सरकार बनने से पहले करीब-करीब 50-52 प्रतिशत थी। वो इन तीन सालों में 80 प्रतिशत को पार कर चुकी है। और विशेष रूप से महिलाओं के बैंक खातों में बढ़ोत्तरी हुई है। सालों से बात होती आई है कि अलग-अलग देशों में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन भारत में नहीं है।

जब हम सरकार में आए तब हाल कुछ ऐसा ही था। देश का सामान्य जन सामाजिक सुरक्षा से वंचित था। ये बात सही है कि भारत में परम्परागत रूप से संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। एक-एक परिवार में 20-20, 25-25, 30-30 लोग साथ रहते थे; तो सामाजिक व्यवस्था थी सुरक्षा की। लेकिन अब परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, बूढ़े मां-बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था बदल रही है।

हमने इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए इस नई परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत लाइफ कवर और रूपे कार्ड, एक्सीडेंट कवर के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ-साथ जन सुरक्षा योजनाओं के तहत दो बीमा और एक पेंशन योजना शुरू की गई।

इसी का परिणाम है कि 2014 में जहां सरकार की बीमा योजनाओं के तहत सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख यानी 5 करोड़ से भी कम subscribers थे, आज 2018 में जन सुरक्षा की योजनाओं के अंतर्गत ये संख्या दस गुना से ज्यादा बढ़ गई है और करीब-करीब 50 करोड़ subscribers हो चुके हैं।

जन सुरक्षा के तहत शुरू की गई योजनाएं अलग-अलग परिस्थितियों के लिए हैं। और काफी कम प्रीमियम पर शुरू की गई हैं। ताकि देश में हर क्षेत्र हर तबके में, हर आयु वर्ग से जुड़े लोग इनका लाभ उठा सकें।

मैं आज जिन लोगों से बात करने वाला हूं- मैं जानता हूं कि ये योजनाएं ऐसी हैं कि जिनके साथ दर्द जुड़ा हुआ है, पीड़ा जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा सदमा जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने इस संकट की घड़ी को झेला है, कठिन समय से गुजरे हैं, उनको इस योजना से कैसे मदद मिली है। जब उनकी बात देश के और हमारे भोले-भोले गरीब नागरिक सुनते हैं तो उनका विश्वास बढ़ करके उनको भी लगता है कि हां इस योजना का भी मुझे लाभ होना चाहिए। और इसलिए एक प्रकार से दुख को बार-बार स्मरण करना भी दुख देता है, लेकिन कभी-कभी किसी व्यक्ति के दुख में से संकट की घड़ी में जो मदद मिली है, वो अगर और लोग जानते हैं तो वो भी संभावित संकटों से बचने का रास्ता खोज सकते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियो देखा होगा आपने कि इन घटनाओं को सुनकर हम सब को दुख तो होता है लेकिन किसी व्यक्ति के चले जाने से उसके परिवार को जो क्षति होती है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में परिवार को आर्थिक संबल मिल जाए, इस घड़ी में वो कुछ पल के लिए टिक जाएं तो फिर वो अपना रास्ता खोज लेता है। और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई।

इस योजना के तहत सिर्फ, और मैं समझता हूं मेरे देशवासी इस बात को समझें, सिर्फ 330 रुपये, इतने से 2 लाख रुपये का बीमा का कवर उपलब्ध हो जाता है। 330 रुपये प्रतिवर्ष, मतलब की एक दिन में एक रुपये से भी कम। यानी इतने कम पैसों में आज बाजार में कुछ मिलता भी नहीं है। ऐसे समय इसका लाभ कैसे लें। इस योजना में अब तक साढ़े पांच करोड़ लोगों ने इसके साथ अपना फायदा उठाया है और मुसीबत में लोगों को करोड़ों रुपयों का क्लेम भी मिल चुका है। आइए कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके पास चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं।

हम सब देख रहे हैं कि संकट कुछ कह करके नहीं आता है। कभी सूचना दे करके मुसीबत नहीं आती है और न ही मुसीबत आप अमीर हैं तो आएगी और गरीब हैं तो नहीं आएगी और गरीब हैं तो आएगी अमीर हैं तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है; वो तो कहीं पर भी आ सकती है। लेकिन हम इन दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत 12 रुपये सालाना यानी मात्र एक रुपये प्रतिमाह के प्रीमियम से 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अब तक इस योजना को करीब-करीब 13-14 करोड़ से अधिक लोगों ने इसे अपनाया है। ये संख्या यानी 13-14 करोड़, अगर दुनिया में हम मेक्सिको देश देखें या जापान देश देखें तो उस देश की कुल जो आबादी है, उससे भी हमारे यहां इस सुरक्षा कवच वालों की संख्या ज्यादा है। इतना व्यापक कवरेज है और इतने कम समय में इतनी भारी संख्या में लोगों का इससे जुड़ना ये दिखाता है कि लोगों में बीमा और उसके लाभ को लेकर काफी जागरूकता आई है।

जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके पूरे परिवार के सामने संकट खड़ा हो जाता है। सारे सपने बिखर जाते हैं। योजना बनाई हो, दो साल में करेंगे, तीन साल में करेंगे; सब धरा का धरा रह जाता है। इसके बावजूद काफी बार देखा गया है कि लोग बीमा को neglect करते रहते हैं। कई बार ऐसे भी रहते हैं बीमा करवा

लेंगे, हो जाएगा, बहुत समय है, जरूरत ही क्या है। आज पूरा देश देख रहा है और मैं चाहता हूं कि बीमा को लेकर इस तरह की मानसिकता बदले। अधिक से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ें।

कुछ साल पहले रोज कमाने वाले और रोज कमा कर खाने वाला इंसान बीमा के बारे में सोचता तक नहीं था और इसका कारण था बीमा के प्रीमियम में लगने वाली धनराशि। अब वो अपनी आमदनी से आज की आवश्यकताएं पूरी करें या उसे भविष्य की चिंता में लगा दे, यह असमंजस बना ही रहता था। ऐसे लोग जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या दूसरा कोई छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन चलाते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस के बारे में सोचना भी नामुमकिन होगा।

आज इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया है और मेरे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, हमारी बहन-बेटियां, उनके लिए बनाया है। बस एक रुपये प्रतिमाह पर लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा पहुंचाई है। अब तक समाज का जो तबका अपना भविष्य भगवान भरोसे छोड़कर चलता था, अब उसने उसमें बीमा का भरोसा भी जोड़कर रखा है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं।

देखिए, वृद्धावस्था जीवन का एक अहम पड़ाव है। एक ऐसा समय है जब हमें कई चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस समय में आर्थिक तौर पर हम आत्मनिर्भर रहें, पेंशन की कल्पना इसी को उद्देश्य में रखकर की गई थी। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और उनके आशीर्वाद के बल पर हम सब इस देश को आगे ले जाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। ये सरकार हमारे बुजुर्गों के लिए प्रतिबद्ध सरकार है और इसके लिए सरकार ने उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके आर्थिक मोर्चे तक सभी सुविधाओं को सरल बनाने का काम किया है।

वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए इनसे निपटने के लिए पिछले चार वर्षों में कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं। पिछले वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री वय-वंदना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के नागरिकों को 10 साल तक आठ पर्सेंट eight percent सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। ब्याज में उतार-चढ़ाव कुछ भी हो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आने दिया जाता है।

यदि रिटर्न eight percent से कम आती है तो सरकार खुद की तिजोरी से उस की भरपाई कर देती है, पेमेंट कर देती है। इस स्कीम के अंदर वरिष्ठ नागरिक मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर रिटर्न का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। अभी तक लगभग तीन लाख से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार Senior Citizens को Tax incentives भी दे रही है। उनके लिए आय पर टैक्स में छूट की मूल सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। इसके साथ-साथ Interest पर deduction की सीमा जो पहले 10 हजार थी उसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। यानी अब जमा रकम से मिले 50 हजार रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

इस तरह से वरिष्ठ नागरिकों, उनके लिए जितनी पहल की गई, उनका सबका लाभ क्या हुआ, इसे अगर हम आंकड़ों में हिसाब से देखें तो मान लीजिए कि एक वरिष्ठ नागरिक, एक हमारा सीनियर सिटीजन जिनकी सालाना आय पांच लाख है, तो 2013-14 में, हमारे आने से पहले उनको लगभग 13- साढ़े 13 हजार 390 रुपये टैक्स बनता था। लेकिन जबसे हम सरकार में आए, हमने उसका सारा फार्मूला बदल दिया।

2019-19 में सो सिर्फ two thousand six hundred रह गया। यानी 13 हजार से ज्यादा था अब सिर्फ 2600 है यानी one-third हो गया है, यानी कितना बड़ा परिवर्तन आया है। न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है।

हम सब जानते हैं कि उम्र बीतने के साथ-साथ हेल्थ संबंधी-स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आना शुरू हो जाती हैं। दवाइयां और इलाज का खर्चा बढ़ जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए जन औषधि योजना शुरू की गई ताकि दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हों। इसी तरह से स्टेंट की कीमतें भी कम की गईं। घुटने का ऑपरेशन भी पहले के मुकाबले सस्ता और किफायती हो गया है।

पहले senior citizens को, वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवित होने का खुद जाकर प्रमाण देना पड़ता था। लेकिन अब इसे भी सरल बनाते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण की व्यवस्था शुरू की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं सरल और सहज उपलब्ध हों, उनके आसपास ही उपलब्ध हों ताकि उन्हें ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। वे स्वस्थ रहें और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें। हमने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है।

वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े और जीवन गौरवपूर्ण हो। पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि मिलती रहे। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत अब तक एक करोड़ से अधिक subscribers हैं जिनमें से करीब 40 प्रतिशत ये हमारी अर्चना बहन जैसी सारी बहनें हैं। इसमें अब तक चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा की जा चुकी है।

कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीन योजनाओं के माध्यम से केवल तीन वर्ष में करीब 20 करोड़ लोगों को बीमा योजनाओं के सुरक्षित नेट के अंतर्गत लाया गया है। और इनमें से 52 प्रतिशत- 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग हमारे गांवों के हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं।

सभी योजनाओं के मूल में दो बातें अहम हैं- पहला कि सभी को बीमा कवर मिले और कम से कम प्रीमियम पर मिले, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है, गरीबों के कल्याण को महत्व देती है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अभी हमने अलग-अलग योजना के लाभार्थियों से सुना कि कैसे मुश्किल समय में उनके और उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिली, उन्हें एक सहारा मिला।

मैं मानता हूं कि उनकी कहानियां हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये दिखाता है कि बीमा सुरक्षा हम सभी के लिए कितना जरूरी है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सब भी इन बीमा योजनाओं का लाभ लें और साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति हो, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति हो, आप उन्हें भी इन योजनाओं के बारे में बताएं, इनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

जितने लाभार्थी यहां पर हैं, आप लोग तो इनकी उपयोगिता के जीवंत उदाहरण हैं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप अपने आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। मैं आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस जा करके खुद को उसमें enrol करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं।

अटल पेंशन योजना के लिए आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर खुद को उसमें दर्ज करा सकते हैं, enrol करवा सकते हैं। और प्रधानमंत्री वय-वृद्धता योजना के लिए देश भर के किसी भी एलआईसी ऑफिस में जाकर इसका आप लाभ ले सकते हैं।

मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं। Senior citizens के लिए कैसी-कैसी योजनाएं हैं, वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, इसके लिए ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन मेरे देश के Senior citizens भी इतने सम्मान से जीने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, इसकी अभी बाहर चर्चा भी नहीं हुई है। जब मैंने देशवासियों को लालकिले से कहा था कि गैस की सब्सिडी की क्या जरूरत है सबको, छोड़ दीजिए ना। और इस देश के एक करोड़ – सवा करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी।

अभी रेलवे में हमारे जो Senior citizens हैं उनको रेलवे की टिकट में कुछ पैसे की राहत मिलती है, लेकिन रेलवे वालों ने अपने फॉर्म में लिखा है कि क्या आप इस सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्या? आप पूरा टिकट का पैसा देना चाहते हैं क्या?

हम सबको गर्व होगा मेरे देश के लाखों Senior citizen, जिनको इसका लाभ मिल सकता था, रेलवे की टिकट का पैसा कम में वो सफर कर सकता था लेकिन देश के लिए लाखों ऐसे Senior citizens आगे आए जिन्होंने रेलवे में जो उनको सब्सिडी मिलती थी टिकट में, वो लेने से मना कर दिया, पूरा पैसा दिया और सफर करा। कोई ढोल नहीं पीटा गया है, कोई अपील नहीं की गई है। न कभी मैंने भी चर्चा की है। सिर्फ एक फॉर्म पर लिखा था, लेकिन उन्होंने एक सम्मान से जीने वाले हमारे Senior citizen ने इतना बड़ा त्याग किया, ये देश के लिए छोटी खबर नहीं है।

और जब मेरे देश के लोग इतना सारा करते हैं, मेरे Senior citizen लोग इतना करते हैं तो हम सबको भी आपके लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करने का मन करता है, कुछ अच्छा करने का मन करता है। आइए हम सब मिल करके हमारे देश के गरीबों का भला हो, हमारी माताओं-बहनों का कल्याण हो, हमारे वयोवृद्ध-अपोवृद्ध सभी महानुभावों को गौरवपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो, उसके लिए प्रयत्न करते रहें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद।

अतुल तिवारी / हिमांशु सिंह / निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1536898) आगंतुक पटल : 558

प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रधानमंत्री की ग्रामीण विद्युतीकरण के लाभार्थियों से संवाद का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 19 JUL 2018 7:36PM by PIB Delhi

आज मुझे देश के उन 18 हजार गांव के आप सब बंधु से मिलने का मौका मिला है, जिनके यहां पहली बार बिजली पहुंची है। सदियां बीत गईं अंधेरे में गुजारा किया और शायद सोचा भी नहीं होगा कि आपके गांव में कभी उजाला आएगा कि, नहीं आएगा। आज मेरे लिये ये भी खुशी की बात है कि मुझे आपकी खुशियों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान बिजली आने के बाद जीवन में आए बदलाव की बातें ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग पैदा होते ही उजाला देखते आए हैं, जिन्होंने कभी अंधेरा देखा नहीं है, उनको ये पता नहीं होता कि अंधेरा हटने का मतलब क्या होता है। रात को बिजली होनी घर में या गांव में इसका मतलब क्या होता है। जिन्होंने कभी अंधेरे में जिन्दगी गुजारी नहीं, उनको पता नहीं चलता है। हमारे यहां उपनिषदों में कहा गया है, “तमसो मा ज्योतिर्गमय।।” यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो।

आज मुझे देश भर के उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश का सफर तय करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सालों के अंधेरे के बाद एक तरह उस गांव का जीवन अब रौशन हुआ है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, जिससे हमारे स्वयं की, हमारे परिवार की, हमारे समाज और राष्ट्र की तरक्की का रास्ता तैयार हो। लेकिन आपके 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे हमेशा-हमेशा के लिये निकल जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। क्या बचे हुए 12, 14 घंटों में आप उतना ही कार्य कर सकेंगे, जितने 24 घंटों में करते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि मोदी जी क्या पूछ रहे हैं और ऐसा किस प्रकार संभव है कि किसी के पास एक दिन में 24 घंटे की जगह मात्र 12, 14 घंटे का समय हो। देशवासियों आपको भले ये सच न लगता हो, लेकिन हमारे देश के सुदूर पिछड़े इलाकों में हजारों गांव में रहने वाले लाखों परिवारों ने दशकों तक इसे जिया है। ऐसे गांव जहां आजादी के इतने वर्ष बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी और वहां रहने वालों का जीवन सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच सिमट कर रह गया था। सूरज की रौशनी ही उनके काम करने के घंटे तय करती थी। फिर चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, खाना पकाना हो, खाना खिलाना हो या और घर के छोटे मोटे काम हों। देश को आजाद हुए कितने दशक बीत गए। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम सरकार में आए तब देश के 18000 से अधिक गांव ऐसे थे जहां बिजली थी ही नहीं। बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर के आखिर ऐसी कौनसी बाधा थी जिसे पार करके पिछली सरकारें अंधियारे में डूबे हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंचा सकी। पिछली सरकारों ने बिजली पहुंचाने के वादे तो बहुत किये, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। 2005 यानि करीब – करीब आज से 13 साल पहले उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2009 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचा देंगे ये वादा किया था और इतना ही कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष ने तो इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2009 तक हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कही थी। अच्छा होता जो अपने आपको बड़े जागरूक और जनहितकारी मानने वाले लोग होते हैं। उन्होंने 2009 में गांव में जाकर के पूछताछ की होती, रिपोर्ट तैयार किये होते, सिविल सोसायटी की बात कही होती, तो हो सकता है कि 2009 नहीं 2010 में हो जाता 2011 में हो जाता, लेकिन उस समय वादे पूरे नहीं हुए। इसको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं था। और आज हम जब वादों को गंभीरता से लेते हैं, तो आज ये खोजने का प्रयास होता है, अरे दूढ़ो

यार इसमें कमी कहाँ है। मैं मानता हूँ यही लोकतंत्र की ताकत है। हमलोग अच्छा करने का लगातार प्रयास करें और जहाँ कमी रह जाती है, उसको उजागर करके उसको ठीक करने का प्रयास करें। जब हम सब मिलकर के काम करते हैं, तो अच्छे परिणाम भी निकलते हैं।

15 अगस्त, 2015 को मैंने लालकिले के प्राचीर से कहा था। और हमने लक्ष्य तय किया कि हम एक हजार दिन के भीतर देश के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। सरकार के बिना किसी देरी के इस दिशा में काम करना शुरू किया। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूर्व से लेकर के पश्चिम तक देश के हर हिस्से में जो भी गांव बिजली की सुविधा से वंचित थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वहाँ बिजली पहुंचाने के कार्य में हम जुट गए। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया। इस योजना में गांवों, बस्तियों के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ-साथ डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने और किसानों को बिजली सप्लाई के लिये अलग फेडर की व्यवस्था को भी आरंभ कर लिया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि देश के सभी गांव और उससे जुड़ी बस्तियां चाहे छोटी हो या बड़ी उन्हें इस योजना के तहत एक के बाद एक शामिल करते जाएं और उजाला का विस्तार होता चला गया।

कोई भी गांव या बस्ती चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम हो, बिजली सुविधा से वो वंचित न रहे इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। जहाँ पर ग्रिड से जुड़ना संभव न हो उन गांवों पर और उन बस्तियों में ऑफग्रिड माध्यम से बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। 28 अप्रैल 2018 यह भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। मणिपुर का लाइसांग गांव पावर ग्रिड से जुड़ने वाला आखिरी गांव था। यह दिन हर देशवासी के लिये गर्व का क्षण था। और मुझे खुशी है कि आज आखिर में जहाँ बिजली पहुंची है। उस लाइसांग गांव के लोगों से मैं बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्हीं को सुनते हैं, उनका क्या कहना है, ये मणिपुर के सेनापति जिले में हैं

देखिये मेरे प्यारे देशवासियों अभी हमनें अलग-अलग अनुभव सुनें कैसे बिजली आने के बाद जीवन आसान हुआ है। जिन 18000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। उनमें से अधिकतर गांव बहुत ही दूरदराज इलाकों में हैं। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फीले पहाड़ों में हैं, घने जंगलों से घिरे हैं या फिर उग्रवादी एवं नक्सली गतिविधियों के कारण अशांत क्षेत्र में हैं। इन गांवों में बिजली पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये वो गांव हैं जहाँ आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और वहाँ आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पहुंचने के लिये तीन चार दिन पैदल चलना पड़ता है। सामान को अलग-अलग माध्यमों से घोंड़े पर, खच्चर पर, कंधों पर लेकर नावों से ले जाया गया। कई गांव जैसे जम्मू एवं कश्मीर के 35 गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के 16 गांव हेलिकॉप्टर से सामान पहुंचाना था। मैं मानता हूँ कि सरकार की उपलब्धि नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की उपलब्धि है, उस गांव वालों की उपलब्धि है, जो इस काम से जोड़े गए या उन सरकार के छोटे मोटे मुलाजिम जो दिन रात मेहनत की कष्ट उठाया। खम्भे उठा-उठा कर गये। उन छोटे-छोटे सरकार के मुलाजिमों की ये इनका काम है। इलेक्ट्रिशियन हो, टैक्निशियन हो, मजदूर हो। इस कार्य में जुड़े लोगों के अथक प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम हिन्दुस्तान के हर गांव तक रौशनी पहुंचा पाए हैं। मैं उन सभी लोगों को सारे देशवासियों की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको शुभकामनाएं देता हूँ।

आप देखिए मुम्बई की जब भी बात आती है, तो हमें बड़े-बड़े बिल्डिंग रौशनी से जगमगाता शहर और सड़कें याद आती हैं। मुम्बई से थोड़ी दूरी पर एलीफेंटा द्वीपस्थित है। यह पर्यटन का एक बहुत बड़ा आकर्षित केन्द्र है। एलीफेंटा के गुफाएं यूनेस्को के वर्ल्ड हैरिटेज में हैं। वहाँ पर देश विदेश से विशाल संख्या में पर्यटक हरदिन आते हैं। मुझे ये बात जानकर के हैरानी हुई की मुम्बई के इतने पास होने और पर्यटन का इतना बड़ा केन्द्र होने के बावजूद आजादी के इतने वर्षों तक एलीफेंटा द्वीपके गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और न ये मैंने कभी अखबार में पढ़ा, न टीवी पर बड़ा विशेष कार्यक्रम हुआ की वहाँ अंधेरा है। किसी को परवाह नहीं थी। हां अभी खुशी है, अब हम काम कर रहे हैं तो लोग पहुंच जाते हैं की बाईं ओर लाइट नहीं आई, दाईं ओर नहीं आई, पीछेआई, आगे नहीं आई, छोटी आई, बड़ी आई। सब हो रहा है। अगर ये चीजें पहले हुई होती। कोई सोच सकता है 70 साल तक हमारा टूरिस्ट

डेस्टीनेशन एलीफेंटा द्वीप गांवों के लोग अंधेरे की जिन्दगी गुजार रहे थे। समुद्र में केबल बिछा कर वहां तक बिजली पहुंचाई गई। आज उन गांव का अंधेरा छट चुका है। जब इरादे नेक हों, नियत साफ हो और नीति स्पष्ट हो, तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है।

आइये चलते हैं कुछ और इलाके में, आईए सबसे पहले झारखंड चलते हैं....

देखिये भाइयों बहनों पिछली सरकारों ने देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। ये क्षेत्र विकास और विभिन्न सुविधाओं से वंचित रहा। ये इस बात से समझा जा सकता है कि देश के 18000 से अधिक गांव जहां बिजली नहीं पहुंची थी। उनमें से ये आंकड़ा जरा देश को चौंकाने वाला है। उनमेंसे 18000 में से 14,582 यानि करीब-करीब 15000 गांव ऐसे थे जो हमारे पूर्वी क्षेत्र में थे और उनमें भी यानि 14,582 गांव में से 5790 यानि करीब करीब 6000 गांव नॉर्थ ईस्ट में थे, पूर्वांचल के थे पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के थे। आप देखिये, ये आप टीवी पर देखते होंगे, मैंने उसका नक्शा रखा है। जो लाल-लाल टाइप के दिखते हैं आपको ये सारा इलाका अंधेरे में था। अब मुझे बताइए अगर सबका भला करने के लिये सोचते तो ये हाल होता क्या। लेकिन वहां लोग कम हैं पार्लियामेंट की सीटें भी कम हैं। तो उन सरकारों को ज्यादा फायदा नहीं दिखता था। देश की सेवा राजनीतिक फायदे से जुड़ी हुई नहीं होती। देश की सेवा देशवासियों के लिये होती है और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भारत की विकास की यात्रा में और गति आएगी जब हमारे पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहां के समाज का संतुलित विकास भी तेज गति से होगा।

जब हमारी सरकार बनी हम इसी अपरोच के साथ आगे बढ़े और हमने पूर्वोत्तर को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में प्रयास शुरू किया। इसके लिये सबसे पहले आवश्यक था कि वहां के गांवों में बिजली पहुंचे और मुझे खुशी है कि आज न सिर्फ पूर्वी भारत के बल्कि देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। गांव का अंधेरा दूर हो चुका है। बिजली आती है तो क्या होता है। जीवन में क्या बदलाव आता है। आप लोगों से बेहतर इस बात को कौन जान सकता है। मुझे देशवासियों के कई सारे पत्र आते रहते हैं। लोग मुझसे अपने अनुभव शेयर करते हैं। मुझे उनके पत्रों को पढ़कर के काफी कुछ सीखने को मिलता है।

आप कल्पना कर सकते हैं कि बिजली आने से गांव में रह रहे सामान्य जनजीवन में कितना बदलाव आया है। अब गांव के लोगों को समय पर अंधियारे का नहीं इनका स्वयं का अधिकार होता है। अब सूर्यास्त में केवल सूर्य अस्त होता है लोगों का दिन अस्त नहीं होता है। बच्चे दिन डूबने के बाद भी बल्ब की रौशनी में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। गांव की महिलाओं को अब रात का खाना शाम को दोपहर से जो बनाना शुरू करना पड़ता था। खाना अभी बना है जल्दी-जल्दी शुरू कर दो का चक्कर चलता था। उस भय से मुक्ति आई है। हाट, बाजार देर तक रात को खुले मिलेंगे। मोबाइल चार्ज करने के लिये दूरदराज कोई दुकान नहीं तलाश करनी पड़ती। अब रात को दूसरे गांव में मोबाइल छोड़कर आओ और सुबह लेने जाऊं और उसी फोन से रात को कोई गड़बड़ कर दे, तो सारा गुनाह आपका बन जाता आप जेल चले जाते हैं। कैसी-कैसी मुसीबतें थीं। जम्मू-कश्मीर के लोग हमारे बीच में हैं आइये, क्योंकि वहां तो पहाड़ों में बड़ी कठिनाई से ये सारा सामान हेलिकॉप्टर से भेजना पड़ता था, तो मैं चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों से मैं सुनूँ कुछ बातें।

देखिये लाखों लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो जान पा रहे हैं कि जब विकास होता है तो जीवन पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है। कितना बड़ा बदलाव आता है। आज देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। लेकिन हम इतने से संतुष्ट हुए हैं इतना नहीं है, इसलिए अब गांव से आगे बढ़कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने इस देश के हर घर को रौशन करने का संकल्प किया है और इस दिशा में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसका छोटा सा शब्द बनता है सौभाग्य योजना इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत बचे हुए सभी घरों को चाहे वो गांव में हो या शहर में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके तहत चार करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और हम इसके लिए एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। अभी तक इस योजना के तहत करीब 80 85 90 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंच चुकी है। गरीब परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन

बिल्कुल मुफ्त है। वहीं सक्षम परिवारों से सिर्फ 500 रुपये लिए जाएंगे, जिसे कनेक्शन लगाने के बाद दस आसान किस्तों में आप अपने बिजली बिल के साथ चुका सकते हैं। घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम समय में लोगों के घर तक बिजली पहुंचे इसके लिये गांवों में कैम्प भी लगाए जा रहे हैं। जहां मौके पर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर नये कनेक्शन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

इसके अलावा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा आधारित प्रणालियों का प्रावधान भी किया गया है। मैं मानता हूं कि बिजली सिर्फ प्रकाश की ही पूर्ति नहीं करती, बिजली लोगों में आत्मविश्वास भी भर्ती है। एनर्जी ऊर्जा ये एक प्रकार से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अच्छा साधन भी बन सकता है। गांव-गांव तक पहुंची रौशनी सिर्फ सूरज डूबने के बाद का अधियारा नहीं मिटा रही, ये रौशनी गांव और गांव के लोगों के जीवन में तरक्की का उजियारा भर रही है। और इसका प्रमाण है आपकी ये बातें, जिन्हें इस बदलाव के बाद आपने अनुभव किया और हमारे साथ यहां साझा किया। सारे देश ने आपको सुना है। कई गांव और भी है समय की कमी है, संसद चल रही है मुझे पहुंचना है पर कुछ गांवों से नमस्ते जरूर करना चाहूंगा। बस्तर को नमस्ते, अलीराजपुर को नमस्ते, सीहोर को नमस्ते, नवपाड़ा को नमस्ते, सीतापुर को नमस्ते और कभी-कभी आप लोग टीवी में देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे हमारे विरोधियों के भाषण सुनते होंगे। विरोधियों के गाने बजाने वालों को सुनते होंगे। वो कहते हैं देखो इतने घरों में बिजली नहीं, इतने घरों में बिजली नहीं है। आप ये मत समझिए कि हमारी टीका है या हमारी सरकार की टीका है। ये पिछले 70 साल जो सरकार चला रहे थे उनकी टीका है। ये हमारी आलोचना नहीं है ये उनकी आलोचना है कि इतना काम बाकी रखा है। हम तो उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

और इसलिए अगर चार करोड़ परिवारों में बिजली नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में पहले बिजली थी, आपके गांव में पहले बिजली थी और मोदी सरकार ने आकर के सब काट दिया, खंभे उखाड़कर के ले गया, तार सारे ले गये, ऐसा नहीं है। पहले कुछ था ही नहीं। हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जो लोग बड़े उत्साह में आकर के हमारे विरोधी हमको गालियां देते रहते हैं, उस परिवार में बिजली नहीं पहुंची, उसके घर में बिजली नहीं पहुंची, उधर खम्भा नहीं लगा। पहले किसीने नहीं लगाया था। हम कोशिश कर रहे हैं और आपका साथ सहयोग रहा और छोटे-छोटे लोग जिन्होंने मेहनत की है हम उनको निराश करने का काम न करें। मोदी को जितनी गालियां देनी है देते रहिए। लेकिन जो छोटे-छोटे लोग मेहनत करते हैं गांव में उजियारा लाने के लिए कोशिश करते हैं। उनका हम मान सम्मान बढ़ाएं, उनका हम गौरव करें उनको काम करने का हौसला बुलंद हो, इसके लिए हम सब प्रयास करें तो फिर देश में जो समस्याएं हैं एक के बाद एक समस्याओं से हम हमारे गांव को, हमारे परिवारों को, हमारे देश को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि आखिरकार हम सबका काम है समस्याएं गिनते जाना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समस्याओं से मुक्ति दिलाने के रास्ते खोजना।

मुझे विश्वास है कि परमात्मा हम सबको शक्ति देगा। इरादे हमारे नेक हैं। आप सबके प्रति हमारे दिल में इतना प्यार है कि जितना हम आपके लिये करें कम है। हम करते रहेंगे। मैं आखिर में आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। आइए हम एक वीडियो देखें उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा हूं।

AKT/VJ/BM/SA

(रिलीज़ आईडी: 1539370) आगंतुक पटल : 1220

प्रधानमंत्री कार्यालय

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में "शहरी लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मिंग" समारोह में प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2018 11:15PM by PIB Delhi

देश के अलग-अलग कोने से आए हुए सभी प्यारे भाइयो और बहनों।

उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूँ और इसलिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। देश के अलग-अलग कोने से आप पधारे हैं, मुझे विश्वास है कि आपने इस ऐतिहासिक नगरी का, उसके आतिथ्य का और लखनवी लहजे का भी आनंद लिया होगा। साथियो, आप सभी इसी बदलाव को अंगीकार करने वाले, जमीन पर चीजों को उतारने वाली टोली हैं। मेयर हो, कमीशनर हो या फिर CEO हो; आप देश के उन शहरों के प्रतिनिधि हैं जो नई सदी, नए भारत और नई जेनरेशन की आशा और आकांक्षाओं के भी प्रतीक हैं। बीते तीन वर्षों से आप करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने में कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ जुटे हैं।

कुछ देर पहले मुझे यहां जो प्रदर्शनी लगी, उसे देखने का अवसर मिला। वहां देशभर में चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। Smart City Mission में बेहतरीन काम करने वाले कुछ शहरों को पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ भाई-बहनों और बेटियों को उनके अपने मकान की चाबियां भी सौंपी गईं और चाबियां मिलने पर जो चमक उनके चेहरे पर थी, उज्ज्वल भविष्य का जो आत्मविश्वास उनकी आंखों से झलक रहा था, वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।

ऐसे अनेक लाभार्थियों से यहां मंच पर आने से पहले मुझे बातचीत करने का मौका मिला। देश के गरीब, बेघर भाई-बहनों के जीवन को बदलने का ये अवसर और बदलते हुए देखना; ये सचमुच में जीवन में एक बहुत बड़ा संतोष देने वाला अनुभव है। जिन शहरों को पुरस्कार मिले हैं, उन शहरों के हर नागरिक को और जिनको अपना घर मिला है, उन सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई है, बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं।

लेकिन आप लोगों ने मार्क किया होगा जब मैं अवार्ड दे रहा था, सब लोग आ रहे थे, मार्क नहीं किया होगा; सिर्फ दो ही पुरुष मेयर हैं बाकी सारी महिला मेयरे हैं। हमारी बहनों ने जिस जीवट के साथ इस काम को किया है जरा तालियां उन बहनों के लिए।

साथियो, शहर के गरीब, बेघर को पक्का घर देने का अभियान हो, सौ स्मार्ट सिटी का काम हो या फिर 500 AMRUT Cities हों; करोड़ों देशवासियों को जीवन को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने का हमारा संकल्प हर तीन साल बाद और अधिक मजबूत हुआ है। आज भी यहां उत्तर प्रदेश के शहरों को स्मार्ट बनाने वाली अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और मुझे बताया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देशभर में लगभग

सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है और 52 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं पर काम तेज गति से चल रहा है। इस मिशन का लक्ष्य है शहरों में रहने वाले गरीब, निम्न-मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को आसान बनाना, उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाएं देना। स्मार्ट सिटी में इन सुविधाओं को देने के लिए integrated command centers; ये उनकी आत्मा की तरह हैं; यहीं से पूरे शहर की व्यवस्थाओं का संचालन होना है, शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जानी है।

साथियों, मिशन के तहत चयनित 100 शहरों में से 11 शहरों में integrated command and control centers ने काम करना शुरू कर दिया है और अगले कुछ महीनों में ही 50 और शहरों में ये काम पूरा करने का प्रयास चल रहा है। ये प्रयास परिणाम भी देने लगे हैं और मुझे बताया गया है कि गुजरात में राजकोट शहर में इस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था से जो कुछ परिस्थिति बदली है, पिछली दो quarter में क्राइम रेट में काफी बड़ी मात्रा में कमी आई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की वजह से गंदगी फैलाने और सार्वजनिक जगह पर कूड़ा जलाने जैसी कई प्रवृत्तियों में भी इसके कारण कमी आई है।

भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में इसके कारण वृद्धि देखी गई है। अहमदाबाद में बीआरटीएस कॉरिडोर- उसमें फ्री वाई-फाई से बसों में आने-जाने वालों की संख्या अपने-आप बढ़ने लगी है। विशापत्तनम में सीसीटीवी और जीपीएस से बसों को online track किया जा रहा है। पुणे में लगभग सवा सौ जगहों पर emergency call bells लगाए गए हैं जहां एक बटन दबाने भर से ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना मिल जाती है। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं आज काम करना शुरू कर चुकी हैं। बहुत जल्द ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद और ये हमारा लखनऊ; इसमें भी ऐसी सुविधाएं, आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

भाइयो और बहनों transforming the landscape of Urban India का हमारा मिशन और लखनऊ का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। लखनऊ शहर देश के शहरी जीवन को नई दिशा देने वाले महापुरुष श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। हमारे प्रेरणा स्रोत और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये लम्बे समय तक संसदीय क्षेत्र रहा है। आजकल अटल जी की तबियत ठीक नहीं है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना पूरा देश कर रहा है। लेकिन अटलजी ने जो बीड़ा उठाया था उसको एक अलग बुलंदी देने की तरफ हमारी सरकार, करोड़ों हिन्दुस्तानी तेज गति से उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं।

साथियों, अटलजी ने एक प्रकार से लखनऊ को देश के शहरी जीवन के सुधार की प्रयोगशाला बनाया था। आज आप यहां लखनऊ में जो flyover, bio technology park, scientific convention centers, ये जो आ देख रहे हैं, ये लखनऊ के इर्द-गिर्द लगभग 1000 गांवों को लखनऊ से जोड़ने वाली जो सड़कें देख रहे हैं। ऐसे तमाम काम लखनऊ में उनके एमपी के रूप में, उनका जो vision था; उसका परिणाम है। आज देश के 12 शहरों में मेट्रो या तो चल रही है या फिर जल्द शुरू होने वाली है। यहां लखनऊ में भी मेट्रो के विस्तार का काम चल रहा है। Urban transport में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली इस व्यवस्था को सबसे पहले दिल्ली में जमीन पर उतारने का काम भी अटल बिहार वाजपेयी जी ने किया था। दिल्ली मेट्रो की सफलता आज पूरे देश में दोहराई जा रही है।

साथियों, अटलजी कहा करते थे कि बिना पुराने को संवारे नया भी नहीं संवरेगा। ये बात उन्होंने पुराने और नए लखनऊ के संदर्भ में कही थी। यही आज के हमारे AMRUT और उसका नाम भी अटलजी से जुड़ा हुआ है; ये 'अमृत' जो हम कह रहे हैं- 'अमृत योजना'- उसका पूरा शब्द है Atal Mission for rejuvenation and urban transformation, और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए ये हमारी प्रेरणा है।

इसी सोच के साथ अनेक शहरों में दशकों पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। इन शहरों में सीवरेज की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट में सुधार, झील, तालाब और पार्कों के सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था, इसको बल दिया जा रहा है।

साथियो, शहर की झुगियों में खुले में जीवन बसर करने वाले गरीब, बेघर भाई-बहनों को उनका अपना घर देने की योजना आज चल रही है, इसकी शुरूआत भी अटलजी ने ही की थी। साल 2001 में बाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना देशभर में अटलजी ने प्रारंभ की थी। यहीं, लखनऊ में ही इस योजना के तहत करीब 10 हजार भाई-बहनों को अपना मकान मिला था। आज जो योजनाएं चल रही हैं, उसके मूल में भावना वही है, लेकिन हमने speed, scale और quality of living को हम एक अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार 2022 तक हर सिर पर छत देने का प्रयास कर रही है। जब आजादी के 75 साल हों, तब हिन्दुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो, जिसका अपना घर न हो।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीते तीन वर्षों में शहरी इलाकों में 54 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांवों में भी एक करोड़ से अधिक मकान जनता को सौंपे जा चुके हैं। आज जो मकान बन रहे हैं उनमें शौचालय भी है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी है, उजाला के तहत एलईडी बल्ब भी लगा है; यानी एक पूरा पैकेज उनको मिल रहा है। इन घरों के लिए सरकार ब्याज में राहत तो दे ही रही है, पहले के मुकाबले अब घरों का एरिया भी बढ़ा दिया गया है।

साथियो, ये जो मकान दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ गरीब बेघर के सिर पर छत ही नहीं है बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का ये जीता-जागता सबूत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी मकान दिए जा रहे हैं, माताओं और बहनों के नाम पर दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 87 लाख मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर या फिर साझेदारी में की जा चुकी है। वरना हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी रही- किसी भी परिवार में जाइए, जमीन किसके नाम पर- पति के नाम पर, पिता के नाम पर, बेटे के नाम पर। घर किसके नाम पर- पति के नाम पर, बेटे के नाम पर। स्कूटर लाया किसके नाम पर- बेटे के नाम पर; उस महिला के नाम पर कुछ नहीं है।

स्थिति को हमने बदला है। और पहले वो हमारे यहां तो कहा भी जाता था- अब गली से गुजरने वाले से ये नहीं पूछेंगे कि फलां मकान का मालिक कौन है बल्कि ये पूछेंगे कि इस मकान की मालकिन कौन है? ये बदलाव समाज की सोच में आने वाला है।

मैं योगीजी और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि वो गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली इस योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। वरना मुझे इससे पहले की सरकार का भी अनुभव है। 2014 के बाद योगीजी आने तक वो दिन कैसे रहे हैं, मैं भलीभांति जानता हूं और मैं जनता को बार-बार याद दिलाता हूं। गरीबों के घर के लिए कैसे हमें केंद्र से बार-बार चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं, जब भी मिलना हो तो बात करनी पड़ती थी- अरे भाई कुछ करो, हम पैसे देने को तैयार हैं। उनको आग्रह करना पड़ता था। लेकिन वो सरकारें ही ऐसी थीं, वो लोग भी ऐसे ही थे। वो अपनी कार्य-परम्परा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। उन्हें तो one point programme था, अपने बंगले को सजाना-संवारना। अब उसमें फुरसत मिले तभी तो गरीब का घर बनेगा ना।

आज एक और बात कहना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया है तो ये बात मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों से तो शेयर करनी चाहिए क्योंकि आपका हक बनता है। आपने सुना होगा इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगाया गया है। और इल्जाम ये है कि मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं भागीदार हूं।

लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयो-बहनों और मेरे देशवासियों, मैं इस इल्जाम को ईनाम मानता हूं और मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं। मैं देश के गरीबों के दुख का भागीदार हूं, मैं मेहनतकश मजदूरों का भागीदार हूं, मैं हर दुखियारी मां की तकलीफों का भागीदार हूं। मैं भागीदार हूं उस मां की पीड़ा का जो इधर-उधर से लकड़ी और गोबर बीनकर चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों और सेहत को खराब करती है। मैं उस हर मां का चूल्हा बदल देना चाहता हूं।

मैं भागीदार हूं उस किसान के दर्द का जिसकी फसल सूखे में या पानी में बर्बाद हो जाती है और वो हताश हो जाता है। मैं उस किसान की आर्थिक सुरक्षा करने का भागीदार हूं।

मैं भागीदार हूं अपने उन बहादुर जवानों के उस जुनून का जो सियाचिन और कारगिल की हड्डी गला देने वाली ठंड से ले करके जैसलमेर और कच्छ की चमड़ी झुलसाने वाले तपते रेगिस्तान में हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं।

मैं भागीदार हूं उस गरीब परिवार की पीड़ा का जो अपने घर में बीमार पड़े व्यक्ति का इलाज कराने में अपनी जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाता है। मैं उस परिवार के लिए सोचता हूं और उसकी सेवा के लिए काम करता हूं।

मैं भागीदार हूं, मैं भागीदार हूं उस कोशिश का जो इसलिए है कि गरीबों के सिर पर छत हो, उन्हें घर मिले, उस घर में उन्हें शौचालय मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले, बिजली मिले। उन्हें बीमार होने पर सस्ती दवाइयां और इलाज मिले, बच्चों को शिक्षा मिलें।

मैं भागीदार हूं, उस कोशिश को जिससे हमारे युवाओं को हुनर मिले, नौकरियां मिलें, अपना रोजगार करने में मदद मिले। हमारे हवाई चप्पल पहनने वाले साधारण नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिले, ये मैं देखना चाहता हूं।

मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं, जैसा कि मुझे गर्व है कि मैं एक गरीब मां का बेटा हूं। गरीबी ने मुझे ईमानदारी और हिम्मत दी है। गरीबी की मार ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। मैंने गरीबी की मार को झेला है, गरीब का दुख-दर्द मैंने करीब से देखा है। हमारे यहां कहा जाता है- 'जिसके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।' जिसने भोगा है वही तकलीफ जानता है और तकलीफ का जमीन से जुड़ा समाधान जानता है।

इससे पहले मुझ पर यह भी इल्जाम लगाया गया था कि मैं चायवाला, मैं अपने देश का प्रधान सेवक कैसे हो सकता हूं? लेकिन ये निर्णय वो लोग नहीं ले सकते हैं, ये निर्णय देश की सवा सौ करोड़ की जनता लेगी। साथियो, भागीदारी को अपमानित करने वाले, यही सोच आज के हमारे शहरों की समस्याओं की जड़ में भी उसी सोच के नतीजे हैं, उसी की बू आ रही है।

स्मार्ट सिटी के लिए हमारे पास प्रेरणाएं भी थीं और पुरुषार्थ करने वाले लोग भी थे। आज खुदाई में मिलने वाले पुराने शहर उदाहरण हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वज शहरों की रचना करते थे। किस प्रकार से उस जमाने में, सदियों पहले, एक प्रकार की उस युग की स्मार्ट सिटी के परोकार भी रहे हैं और शिल्पकार भी रहे हैं। लेकिन राजनीति की इच्छाशक्ति और सम्पूर्णता की सोच के अभाव ने एक बड़ा नुकसान किया।

आजादी के बाद जब नए सिरे से राष्ट्र निर्माण का दायित्व हमारे कंधे पर था, जब जनसंख्या का उतना दबाव भी नहीं था; तब हमारे शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से बसाने का एक बहुत बड़ा अवसर था। आज जितनी दिक्कतें उस समय नहीं थीं, अगर उसी समय प्लान-वे में काम किया होता तो आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, वो नहीं झेलनी पड़तीं। लेकिन बेतरतीब तरीके से शहरों को जो जहां जिसको फैलना था फैलने दिया गया। जाओ, देखो, मेरा घर भरो, तुम अपना कहीं जाओ। एक प्रकार से कंक्रीट का एक जंगल विकसित होने दिया गया। इसका परिणाम आज हिन्दुस्तान का हर शहर भुगत रहा है।

साथियो, एक पूरी पीढ़ी इन अव्यवस्थाओं से जूझते हुए निकल गई और कहीं-कहीं तो दो-दो, तीन-तीन पीढ़ियां निकल गईं और दूसरी इसके कटु अनुभवों का बोझ ले करके चल रही है। और जानकार लोगों की उम्मीद है और वो जाता रहे हैं कि आज लगभग साढ़े सात प्रतिशत की रफ्तार से विकसित होता भारत आने वाले वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में देश का वो हिस्सा जिसकी जीडीपी में 65 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है, जो एक प्रकार से ग्रोथ का इंजन है, वो अगर अव्यवस्थित रहें तो हमारी कैसी रुकावटें खड़ी होंगी ये हम अंदाज लगा सकते हैं और इसलिए इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना अनिवार्य है।

लटकते तार, गंदा पानी उगलते सीवर, घंटों तक लगते ट्रैफिक जाम; ऐसी तमाम अव्यवस्थाएं 21वीं सदी के भारत का परिभाषित नहीं कर सकतीं। इसी सोच के साथ तीन वर्ष पहले इस मिशन की नींव रखी गई थी। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया और तय किया गया कि दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश से इन्हें विकसित किया गया जाएगा। विकास भी ऐसा कि जहां शरीर नया हो लेकिन आत्मा वही हो, संस्कृति जहां की पहचान होगी; स्मार्टनेस, ये उसकी जिंदगी होगी। ऐसे जीवंत शहर विकसित करने की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

साथियों, हमारी सरकार के लिए स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि हमारे लिए एक मिशन है। Mission to transformation, mission to transform, mission to transform the nation, ये मिशन हमारे शहरों को न्यू इंडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करेगा। 21वीं सदी के भारत में विश्वस्तरीय intelligent urban centers खड़ा करेगा। ये देश के उस युवा की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि बेस्ट चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि इसी जेनरेशन के लिए भविष्य की व्यवस्थाओं का निर्माण हो। यहां जीवन Five E पर आधारित हो और Five E यानी Ease of living, Education, Employment, Economy and Entertainment.

और जब भी मैं आप जैसे लोगों जैसे शहर के मेयर से, म्युनिसिपल कमीशनर या CEO से बातचीत करता हूँ तो एक नई आशा सामने आती है। स्मार्ट सिटी मिशन की प्रक्रिया का ढांचा जन-सहभाग, जन-आकांक्षा और जन-दायित्व; इन तीनों पर आधारित है। अपने शहर में इस तरह की योजनाएं शुरू हों, ये शहर के लोगों ने खुद तय किया है। उनके ही विचार शहरों के स्मार्ट सिटी विजन के आधार बने हैं और इन पर आज तेज गति से काम चल रहा है।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि न सिर्फ यहां नई व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है बल्कि फंडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। पुणे, हैदराबाद और इंदौर ने म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये जुटाए। अब लखनऊ और गाजियाबाद में भी बहुत जल्द ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स सरकारों पर आर्थिक निर्भरता को भी कम करने का काम करेंगे। मेरा बाकी शहरों से भी आग्रह है वो इस प्रकार के initiative के लिए आगे आए।

साथियो, शहरों का स्मार्ट होना, सिस्टम का टेक्नोलॉजी से जुड़ना, ये ease of living को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज आप अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं, जिसके कारण अब सामान्य जन को कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। ये कतारें भी तो करप्शन की जड़ थीं। आज आपको कोई बिल भरना हो, किसी सुविधा के लिए एप्लाइ करना हो, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर छात्रवृत्ति, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड जैसी अनेक सुविधाएं आज ऑनलाइन हैं; यानि आज governance भी स्मार्ट हो रहा है जिससे transparency सुनिश्चित हुई है। और इसकी वजह से करप्शन में बहुत बड़ी कमी आ रही है।

साथियो, smart, secure, sustainable और transparent व्यवस्थाएं देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। ये जो भी सिस्टम बनाया जा रहा है ये सबके लिए है। इसमें ऊंच-नीच, पंत, सम्प्रदाय, छोटे-बड़े, ऐसी कोई सीमाएं नहीं हैं, न वो आधार है; सिर्फ और सिर्फ विकास, यही एक मंत्र है। कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जन भागीदारी, राज्यों की भागीदारी, स्थानीय निकायों की भागीदारी से ये सब कुछ संभव हो सकता है। 'सबका साथ-सबका विकास' और टीम इंडिया की ही भावना न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने वाली है।

और मैं आज योगीजी से जब बात कर रहा तो उन्होंने एक अच्छी खबर सुनाई। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो देश में अगर हम हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा करें, कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं। और दुर्भाग्य है कि पहले नेताओं को वोट लेते समय नागरिक याद आते थे। अगर हम सचमुच में नागरिकों की शक्ति और सद्भावनाओं को देखें और उसको टटोलें तो कैसा परिणाम मिलता है, योगीजी मुझे बता रहे थे। आपको मालूम है मैंने एक बार 15 अगस्त पर लालकिले से कहा था- कि अगर आप कमाते-धमाते हैं, एक गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, क्यों लेते हो वो गैस की सब्सिडी? इस देश में सब्सिडी राजनीति से ऐसी जुड़ गई है, कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करता; हमने की और देश को गर्व होना चाहिए करीब-करीब सवा करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी।

अब वो तो बात लालकिले से बोला था लेकिन देश का मिजाज देखिए- रेलवे वालों ने अपना जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है उसमें एक कॉलम बनाई है अभी, नई-नई कॉलम बनाई है, अभी कुछ महीने पहले बनाई है। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया है, ऐसे ही लिख दिया है। और उसमें हमें मालूम है कि रेलवे में जो सीनियर सिटिजन यात्रा करते हैं उनको concession मिलता है, सब्सिडी मिलती है। क्या कमाते-धमाते हैं, कुछ नहीं, आपकी उम्र इतनी हो गई आपको ये लाभ मिलेगा। उन्होंने लिखा- कि अगर आपको, आप कमाते-धमाते हैं और अगर आप ये

जो सब्सिडी है, छोड़ना चाहते हैं, इस कॉलम में Tick mark करिए। मैं- जान करके मुझे खुशी हुई, इतने कम समय में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, किसी नेता का बयान नहीं, कुछ नहीं; इस देश के 40 लाख से ज्यादा लोगों ने रेलवे यात्रा की अपनी सब्सिडी छोड़ दी; ये छोटी बात नहीं है।

आज मुझे योगीजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गांवों में जो लोगों को आवास मिले थे पुराने, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बदली, कुछ लोग वहां से कुछ शहर में चले गए बेटे रोजी-रोटी कमाने गए तो, वहां settle हो गए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने request की लोगों को कि अगर आपकी स्थिति में बदलाव आया है और आपके पास पहले सरकार का दिया हुआ मकान है; अगर आप वो मकान सरकार को वापिस दें तो हम किसी गरीब को allot करना चाहते हैं। मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि मेरे उत्तर प्रदेश के गांवों के 46 हजार (forty six thousand) लोगों ने अपने घर वापिस दे दिए। ये छोटी बात नहीं है जी।

हमारे देश में ऐसी मानसिकता बनी हुई थी कि जैसे सब लोग चोर हैं, सब ऐसा करोगे। ये तो, कोई जरूरत नहीं है, हम देश के नागरिकों पर भरोसा करें, देश चलाने के लिए हमसे भी ज्यादा ताकत मेरे देशवासियों में है, ये हम में विश्वास होना चाहिए। देश को बदलने के लिए किस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं, एक ईमानदारी का माहौल बना है। पहले की तुलना में अब ज्यादा लोग टैक्स देने के लिए आ रहे हैं। नगर के अंदर सुविधाएं अगर दिखती हैं तो लोग टैक्स देने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसको भरोसा हुआ है कि पाई-पाई सही जगह पर खर्च होगी, खुद के बंगलों पर खर्च नहीं होगी तो देश का सामान्य मानवी पैसे देने के लिए तैयार हो गया है।

और इसलिए सब फिर से एक बार आप सभी को इस मिशन के लिए, जो काम आप लोगों ने किया है और जो हमारे देश नगर निगम से सभी महानुभाव आए हैं, उनको भी। मुझे विश्वास है कि अगली बार और भी शहर आगे आएंगे, जो आगे निकल चुके हैं-निकल चुके हैं लेकिन नए लोग आगे आएंगे। नए शहरों में क्षमता पड़ी है, लीडरशिप दीजिए। वहां के कमीशनर हों, वहां के मेयर हों, वहां के CEO हों- जरा जी-जान से एक टारगेट तय कीजिए। आपको भी सम्मानित करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। अब मुझे आपको सम्मानित करने का मौका दीजिए। मैं हिन्दुस्तान के सभी शहरों को निमंत्रित करता हूं, मैं समाने से आपका सम्मान करना चाहता हूं, मुझे आपका सम्मान करने का अवसर दीजिए, इतना उत्तम काम करके आइए।

फिर एक बार सफल होने वालों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, सफलता के लिए प्रयत्न करने वालों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/हिमांशु सिंह/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1541953) आगंतुक पटल : 60

प्रधानमंत्री कार्यालय

रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 23 SEP 2018 6:00PM by PIB Delhi

झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रोपदी मुरमु जी, राज्य के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, केंद्र में मंत्रिपरिषद् के मेरे साथी श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद् के मेरे साथी और इसी धरती की संतान श्रीमान सुदर्शन भगत जी, केंद्र में हमारे साथी जयंत सिन्हा जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के.पॉल, राज्य सरकार के मंत्री रामचंद्र चंद्रमुंशी, संसद में मेरे साथी श्रीमान रामटहल चौधरी जी, विधायक श्रीमान रामकुमार पाहण जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए झारखंड के मेरे प्यारे भाइयो और बहनों।

साथियो, आज हम सभी आज उस विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं जिसका आकलन भविष्य में मानवता की बहुत बड़ी सेवा के रूप में होना तय है। आज मैं यहां सिर्फ झारखंड के विकास को गति देने के लिए नहीं, लेकिन पूरे भारत में जो सपना हमारे ऋषियों-मुनियों ने देखा था, जो सपना हर परिवार का होता है, और हमारे ऋषियों-मुनियों ने सपना देखा था 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः'। हमारे इस सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है।

समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है। गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले। आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस विरसामुंडा की धरती से उठाया जा रहा है।

आज पूरे हिन्दुस्तान का ध्यान रांची की धरती पर है। देश के 400 से अधिक जिलों में ऐसा ही बड़ा समारोह चल रहा है और वहां से सब लोग इस रांची के भव्य समारोह को देख रहे हैं और वे भी इसके बाद वहां इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं।

आज यहां मुझे दो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का भी अवसर मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि आजादी के 70 साल में तीन मेडिकल कॉलेज, साढ़े तीन सौ विद्यार्थी और चार साल में आठ मेडिकल कॉलेज, 1200 विद्यार्थी। काम कैसे होता है, कितने व्यापक प्रमाण में होता है, कितनी तेज गति से होता है, इसका मैं नहीं मानता है कि इसको बड़ा उदाहरण अब और कोई ढूंढने के लिए किसी को जाने की जरूरत है।

भाइयो-बहनों, आज आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना PMJAY आज से लागू हो रही है। इस योजना को हर कोई अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार नाम दे रहा है। कोई इसे मोदी केयर कह रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है। अलग-अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये हमारे देश के दरिद्रनारायण की सेवा का एक महामुला अवसर है। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती है।

देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई-बहनों को पांच लाख रुपये तक का health assurance देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही है।

इस योजना के लाभार्थियों की संख्या, जब हम यहां बैठते हैं तो कल्पना नहीं आती है। पूरा यूरोपीयन यूनियन, 27-28 देश, पूरा यूरोपीयन यूनियन, उसकी जितनी आबादी है, उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है।

पूरे अमेरिका की जनसंख्या, पूरे कनाडा की जनसंख्या, पूरे मैक्सिको की जनसंख्या, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला लें, और जितनी संख्या होती है उससे भी ज्यादा लोगों का आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली है।

और इसलिए अभी हमारे आरोग्य मंत्री नड्डा जी बता रहे थे कि आरोग्य जगत का दुनिया का जो सबसे मान्यता प्राप्त मैगजीन है, वो भी बढ़-चढ़ करके बढ़ाई कर रहा है कि हिन्दुस्तान ने एक game changer, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

और मुझे विश्वास है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग आरोग्य के संबंध में भिन्न-भिन्न योजनाओं के संबंध में सोचने वाले लोग, आरोग्य और अर्थशास्त्र की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और आधुनिक संसाधनों की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और सामान्य मानवी की जिंदगी के बदलाव से समाज जीवन पर होने वाले प्रभावों की चर्चा करने वाले लोग, चाहे वो social scientist हों, चाहे वो मेडिकल साइंस की दुनिया के लोग हों, चाहे वो अर्थशास्त्र के लोग हों, दुनिया के हर किसी को भारत की इस आयुष्मान भारत की योजना का अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इसके आधार पर दुनिया के लिए कौन सा मॉडल बन सकता है, उसके लिए कभी न कभी सोचकर योजनाएं बनानी पड़ेंगी।

मैं इस योजना को मूर्तरूप देने में जिस टीम ने काम किया है, मेरे सारे साथियों ने जो काम किया है, ये काम छोटा नहीं है। छह महीने के भीतर-भीतर दुनिया की इतनी बड़ी योजना, जिसकी कल्पना से ले करके करिश्मा करके दिखाने तक की यात्रा सिर्फ छह महीने में। कभी good governance की जो लोग चर्चा करते होंगे ना, एक टीम बन करके, एक vision के साथ, एक road map ले करके, समयबद्ध उसकी पूर्ति करते हुए और 50 करोड़ लोगों को जोड़ करके, 13 हजार अस्पतालों को जोड़ करके, छह महीने के भीतर-भीतर इतनी बड़ी योजना आज धरती पर ले आना, ये अपने-आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है।

और मैं इसलिए मेरी पूरी टीम को आज सार्वजनिक रूप से सवा सौ करोड़ देशवासियों के सामने जी-भर करके बधाई देता हूं, जी-जान से बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये टीम अब और ताकत से, और अधिक समर्पण से काम करेगी क्योंकि अब तक तो प्रधानमंत्री उनके पीछे लगे रहते थे, लेकिन अब 50 करोड़ों गरीबों के आशीर्वाद उनके साथ हैं। और जब 50 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद इस टीम के साथ हों, गांव में बैठी आशा वर्कर भी जीजान से इस काम को पूरा करने में लग जाएंगे, इसको यशस्वी बना करके रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।

साथियों, गरीबों को आरोग्य का ये जो सुरक्षा कवच प्राप्त हो रहा है, उसे समर्पित करते हुए मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं, योजना तो अच्छी है, हर किसी के लिए है, लेकिन क्या कोई अस्पताल का उद्घाटन करने जाएं और ऐसा कह सकता है कि आपका अस्पताल भरी रहे? कोई नहीं कह सकता। मैं तो अस्पताल का उद्घाटन करने जाऊंगा तो कहूंगा कि आपका अस्पताल हमेशा खाली रहे।

आज आयुष्मान भारत योजना का आरंभ करते समय भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत न आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। किसी की जिंदगी में ऐसी बुरी अवस्था नहीं आनी

चाहिए। और इसके लिए भी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है।

अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे देश के गरीब को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो देश के किसी धनी को मिलती हैं।

भाइयो और बहनों, ये योजना आज से लागू हुई है लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी योजना थी तो trial करना भी जरूरी था। Technology काम करेगी या नहीं करेगी, जो आरोग्य मित्र बनाए हैं वो ठीक से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अस्पताल जो पहले काम करते थे, उसे बदल करके ठीक करें कि नहीं। और इसलिए पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग जिलों में इसका trial चल रहा था। और मुझे विश्वास है कि देश को सही मायने में स्वास्थ्य का अधिकार देने का ये अभियान अपने हर उद्देश्य में सफल रहेगा। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को और मजबूत करेगा।

साथियों, आयुष्मान भारत योजना से एक विशेष अवसर भी जुड़ा हुआ है। जब 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों से मैंने इसका प्रथम चरण प्रारंभ किया था, wellness centre का काम आरंभ किया था, वो बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती थी। आज जब दूसरा महत्वपूर्ण चरण आगे बढ़ रहा है तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म-जयंती 25 सितम्बर को ध्यान में रख करके दो दिन पूर्व आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। आज संडे था, मुझे भी सुविधा थी और इसलिए हमने दो दिन इसको पहले किया। लेकिन आज एक और भी महत्वपूर्ण अवसर है। आज जिस धरती, जिस नाम को लेकर ऊर्जा की अनुभूति करती है, चेतनमंत बन जाती है, जिसके हर शब्द में जगाने का सामर्थ्य रहा है, ऐसे राष्ट्रकवि दिनकर भी जयंती है।

और इसलिए उन महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ समाज के हर प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए, और जिन्होंने जीवनभर गरीबों के लिए सोचा, गरीबों के लिए जिए, गरीबों की गरिमा के लिए अपने-आपको खपा दिया, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हुए आज देश को ये योजना हम दे रहे हैं।

देश में बेहतर इलाज कुछ लोगों तक सीमित न हो। सभी को उत्तम इलाज मिले। इसी भावना के साथ आज ये योजना देश को समर्पित की जा रही है।

भाइयो और बहनों, हमारे देश के health sector की जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि भारत में अगर किसी के इलाज पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें 60 रुपये से ज्यादा बोझ उस परिवार और उस व्यक्ति पर आता है। उसने जो बचा-बचाया है, वो सारा बीमारी में बह जाता है। कमाई का ज्यादातर हिस्सा ऐसे ही खर्च होने के कारण हर साल लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलने की कगार पर होते हैं लेकिन एक बीमारी फिर एक बार उनको गरीबी में वापिस ले जाती है। इसी हालत को बदलने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है।

भाइयो-बहनों, गरीबी हटाओ के नारे, देश आजाद हुआ तबसे हम सुनते आए हैं। गरीबों की आंख में धूल झाँकने वाले, गरीबों के नाम की मालाएं जपते रहने वाले लोग अगर आज से 30-40-50 साल पहले गरीबों के नाम पर राजनीति करने के बजाय गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देते तो देश, आज जो हिन्दुस्तान देख रहा है वैसा नहीं होता। उन्होंने गरीबों के संबंध में सोचने में गलती की। ये मूलभूत गलती ने देश को आज भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गरीब कुछ न कुछ मांगता है। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए, यही उनकी सबसे बड़ी गलत सोच थी। गरीब जितना स्वाभिमान होता है, शायद उस स्वाभिमान को नापने की आपके पास कोई तराजू नहीं है।

मैंने गरीबी को जिया है, मैं गरीबी से पल-बढ़के निकला हूँ। मैंने गरीबों के भीतर के स्वाभिमान को जी भरके जिया है। वो ही स्वाभिमान है जो गरीबी से जूझने की ताकत भी देता है। गरीबी की हालत में भी जीने की ताकत भी देता है। लेकिन न कभी गरीब के स्वाभिमान को समझने का प्रयास किया, न गरीब के सपनों को साकार करने के लिए उसके इरादों को समझने की कोशिश की। और इसलिए हर चुनाव में टुकड़े फेंको, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लो, यही खेल चलता रहा।

हमने बीमारी की जड़ को पकड़ा है। देश गरीबी से मुक्ति की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा- दो-तीन साल के भीतर-भीतर देश में पांच करोड़ परिवार अति गरीबी से बाहर आ गए हैं।

भाइयो-बहनों, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने गरीबों का सशक्तिकरण empowerment of poor, इस पर बल दिया है। और इसलिए गरीब को अगर घर मिलता है तो उसके जीवन की सोच बदलती है। अगर गरीब मां को गैस का कनेक्शन मिलता है तो वो मां जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ दूसरे की बराबरी में खड़ी रहती है।

जब गरीब का बैंक में खाता खुलता है तो वो भी आत्मसम्मान की अनुभूति करता है। पैसे बचाने का इरादा तय कर लेता है। जब गरीब का टीकाकरण होता है, पोषण मिशन का लाभ मिलता है तो गरीब भी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ता है।

आपने देखा होगा, अभी एशियन गेम्स हुए, एशियन गेम्स में अवार्ड लाने वाले कौन थे? गोल्ड मैडल लाने वाले कौन थे? भारत को नई-नई सम्मानजनक स्थिति दिलाने वाले कौन थे? ज्यादातर बच्चे, बेटा हो या बेटी, छोटे गांव में पैदा हुए, गरीब के घर में पैदा हुए, कुपोषण की जिंदगी से गुजारा करते हुए पले-बढ़े, लेकिन मौका मिला तो हिन्दुस्तान का नाम रोशन करके आ गए।

गरीब में भी वो ताकत पड़ी है, उसे पहचानना जरूरी है। और इसलिए हमारी सारी योजनाएं गरीबों का सशक्तिकरण है। देश में एक बहुत बड़ा दूसरा बदलाव आया है। देश में सारी नीतियां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को आधार बना करके की गई हैं। किस जाति को फायदा मिलेगा, जिस जाति से चुनाव जीतने की गारंटी मिलेगी। किस संप्रदाय के लोगों को फायदा मिलेगा, जिस संप्रदाय के लोगों से वोट बटोरने की संभावना बढ़ेगी। किस इलाके को लाभ मिलेगा, जिस इलाके से चुनाव जीतने की संभावना बनेगी। चाहे क्षेत्रीय विकास का मानदंड हो, चाहे सामाजिक बदलाव का मानदंड हो, चाहे साम्प्रदायिक तनावों से मुक्ति का रास्ता हो; पहले सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत समाज की ताकत बढ़ाने के बजाय राजनीतिक दलों की ताकत बढ़ाने के लिए सरकारी खजानों का उपयोग किया। और सरकारी खजानो को बेतहाशा लूटा गया।

हमने वो रास्ता छोड़ दिया है। हम चाहते हैं देश कभी भी उस रास्ते पर वापिस न लौटे। हमारा मंत्र रहा है 'सबका साथ-सबका विकास।' सम्प्रदाय के आधार पर आयुष्मान भारत योजना नहीं होगी। जाति के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगी। ऊंच-नीच के भेदभाव के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगा। 'सबका साथ-सबका विकास' किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी सम्प्रदाय से हो, ईश्वर को मानता हो-न मानता हो, मंदिर में जाता हो, मस्जिद में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, चर्च में जाता हो, कोई भेदभाव नहीं। हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा यही है 'सबका साथ-सबका विकास'।

साथियो, ये योजना कितनी व्यापक है- इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को, उनके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया है। एक हजार तीन सौ- इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा।

पांच लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च, उसमें शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना द्वारा उठाया जाएगा।

इतना ही नहीं, देशभर के हर लाभार्थी को सही से इसका लाभ पहुंचा पाएं, उसका भी प्रभावी इंतजाम किया गया है। आपको इलाज के लिए भटकना न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं। सब कुछ technology के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई जरूरतमंद छूट न जाए इसकी समीक्षा निरंतर चल रही है।

आपको इस योजना में किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपको जो ई-कार्ड मिल रहा है, वही आपके लिए काफी है। ई-कार्ड में आपसे जुड़ी सारी जानकारियां होंगी। इसके लिए आपको तमाम कागजी कार्रवाईयों के फेरे में भी अब पड़ने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा एक टेलीफोन नम्बर और मैं मानता हूं इसको याद रखना चाहिए आप लोगों ने। मेरे सब गरीब परिवारों से खास आग्रह करता हूं, इस नम्बर का जरूर याद रखिए-14555, one four triple five, ये नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका इस योजना में नाम है कि नहीं है। आपके परिवार का नाम है कि नहीं है। आपको क्या मुसीबत है, क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी चीजें, या फिर आपके नजदीक में जो common service centre है, आज देश में तीन लाख common service centre हैं, उन तीन लाख सेंटर किसी को भी दो-तीन किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा। वो जा करके भी वहां से अपनी जानकारियां ले सकते हैं।

साथियों, इन व्यवस्थाओं के साथ ही दो और बड़े सहायक आसपास होंगे। एक-आपके गांव की आशा और एनएनएम बहनों, और दूसरा- हर अस्पताल में आपकी मदद के लिए तैनात रहने वाले प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र। ये प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र अस्पताल में भर्ती होने के पहले से ले करके इलाज के बाद तक आपको योजना का लाभ प्राप्त कराने में आपका पूरा सहयोग देंगे। देश को आयुष्मान बनाने में जुटे हमारे ये समर्पित साथी हर सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।

साथियों, आयुष्मान भारत का ये मिशन सही मायने में एक भारत, सभी को एक तरह के उपचार की भावना को मजबूत करता है। जो राज्य इस योजना से जुड़े हैं, उनमें रहने वाले व्यक्ति अगर उस राज्य के बाहर कहीं जा रहे हैं और वहां अचानक जरूरत पड़ गई तो भी इस योजना का लाभ वो दूसरे राज्य में भी ले सकते हैं।

अभी तक इस योजना से देशभर के 13 हजार से अधिक अस्पताल भी इस योजना में हमारे साथी बन चुके हैं। आने वाले समय में और भी अस्पताल इस मिशन का हिस्सा होने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो अस्पताल अच्छी सेवाएं देंगे, विशेष तौर पर गांव के अस्पताल, तो उन्हें सरकार द्वारा मदद भी दी जाएगी।

भाइयो और बहनों, आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का तो है ही, साथ में ऐसी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है जिससे कि आपको घर के पास ही इलाज की उत्तम सुविधा मिल जाए।

साथियों, आज यहां पर 10 wellness centers का भी शुभारंभ किया गया है। अब झारखंड में करीब 40 ऐसे सेंटर्स काम कर रहे हैं और देशभर में ये करीब दो-ढाई हजार तक पहुंच चुके हैं। अगले चार वर्ष में देशभर में ऐसे डेढ़ लाख wellness centers तैयार करने का लक्ष्य है।

भाइयो और बहनों, ये Health और wellness centers आयुष्मान भारत का बहुत अहम हिस्सा हैं। इन सेंटर्स में छोटी बीमारियों का इलाज, उनके इलाज के लिए दवाइयां तो उपलब्ध होंगी ही, साथ में यहां निःशुल्क अनेक टेस्ट भी कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे गंभीर बीमारियों के लक्षणों की

पहचान पहले ही करने में मदद मिलेगी।

साथियों, सरकार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं बल्कि सम्पूर्णता के साथ एक holistic तरीके से कार्य कर रही है। हर फैसला, हर नीति एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ सरकार affordable health care पर ध्यान दे रही है तो साथ ही preventive health care पर भी जोर दिया जा रहा है। योग हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, open defecation free गांव बनाने का अभियान हो, ये सारे जरिए उन वजहों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है जिनसे गंभीर बीमारियां होती हैं। आपने हाल में पढ़ा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह से तीन लाख बच्चों का जीवन बचने की संभावना पैदा हुई है। नवजात बच्चों का जीवन बचाने से जुड़े आंकड़ें हों या फिर प्रसूता माताओं के, देश बहुत तेजी के साथ आज स्वस्थ भारत बनने की दिशा में कदम उठा रहा है।

सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे अभियान भी शुरू किए हैं ताकि शुरुआती दिनों से ही शरीर को कुपोषित होने से रोका जा सके। वहीं मेडिकल फील्ड के human resource को बढ़ाने पर भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। अनुमान है कि आयुष्मान भारत की वजह से आने वाले तीन वर्षों में देश में लगभग ढाई हजार नए अच्छी क्वालिटी के आधुनिक अस्पताल बनेंगे। इनमें से ज्यादातर टायर-2, टायर-3, छोटे-छोटे कस्बों में बनेंगे। और उसके कारण मध्यम वर्गीय परिवारों को एक नया व्यवसाय का क्षेत्र खुलने वाला है। रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं।

इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में मेडिकल सेवाओं के साथ-साथ बीमा, तकनीकी कौशल, कॉल सेंटर, प्रबंधन, दवा उत्पादन, उपकरण निर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में लाखों-करोड़ों रोजगार की भी संभावनाएं पैदा होने वाली हैं। पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर प्रशिक्षित डॉक्टरों की बहुत बड़ी मांग देश में पैदा होने वाली है। इसके साथ-साथ मेडिकल क्षेत्र से जुड़े start up के लिए भी नए अवसर बनेंगे। लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को इन व्यवस्थाओं को चलाने का, इनसे जुड़ने का अवसर मिलेगा। यानी एक बहुत बड़ा मौका देश के निम्न-मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए भी है।

देश के गांवों, कस्बों, टीयर-1, टीयर-2 शहरों में health infrastructure को मजबूत करने के लिए, उसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। बीते चार वर्षों में देश में 14 नए एम्स की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हर राज्य में कम से कम एक एम्स को बनाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही देश में इस समय 82 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज आज बनाए जा रहे हैं। सरकार का जोर है देश की तीन संसदीय या चार संसदीय सीटों के बीच में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो।

इसी प्रयास के तहत आज यहां भी 600 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले दो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। कोडरमा और चायबासा में बनने वाले इन मेडिकल कॉलेज में करीब 400 बेड की नवीं सुविधा जुड़ने वाली है।

भाइयो और बहनों, बीते चार वर्षों में देशभर में मेडिकल के लगभग 25 हजार अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नई सीटें जोड़ी गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले चार-पांच वर्षों के दौरान देश में एक लाख नए डॉक्टर तैयार करने की क्षमता विकसित हो। यानी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए infrastructure और human resource, दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है।

साथियो, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च, खर्च नहीं वो निवेश होता है। अच्छी शिक्षा और कौशल के अभाव में समाज और देश का विकास संभव नहीं है। उसी तरह नागरिक अस्वस्थ हो, तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता।

साथियो, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस योजना से जुड़े हर व्यक्ति के प्रयासों से आरोग्य मित्र और आशा, एएनएम बहनों के सहयोग से, हर डॉक्टर, हर नर्स, हर कर्मचारी, हर सर्विस प्रोवाइडर की समर्पित भावना से हम इस योजना को सफल बना पाएंगे, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहें, आयुष्मान रहें।

इसी कामना के साथ मैं प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना आज रांची की धरती से, भगवान बिरसामुंडा की धरती से सवा सौ करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूँ।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत माता की - जय

भारत माता की - जय

भारत माता की - जय

मैं बोलूंगा आयुष्मान, आप बोलिए भारत।

आयुष्मान - भारत

आयुष्मान - भारत

आयुष्मान - भारत

आयुष्मान - भारत

आयुष्मान - भारत

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/ वंदना जाटव/ निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1547034) आगंतुक पटल : 998